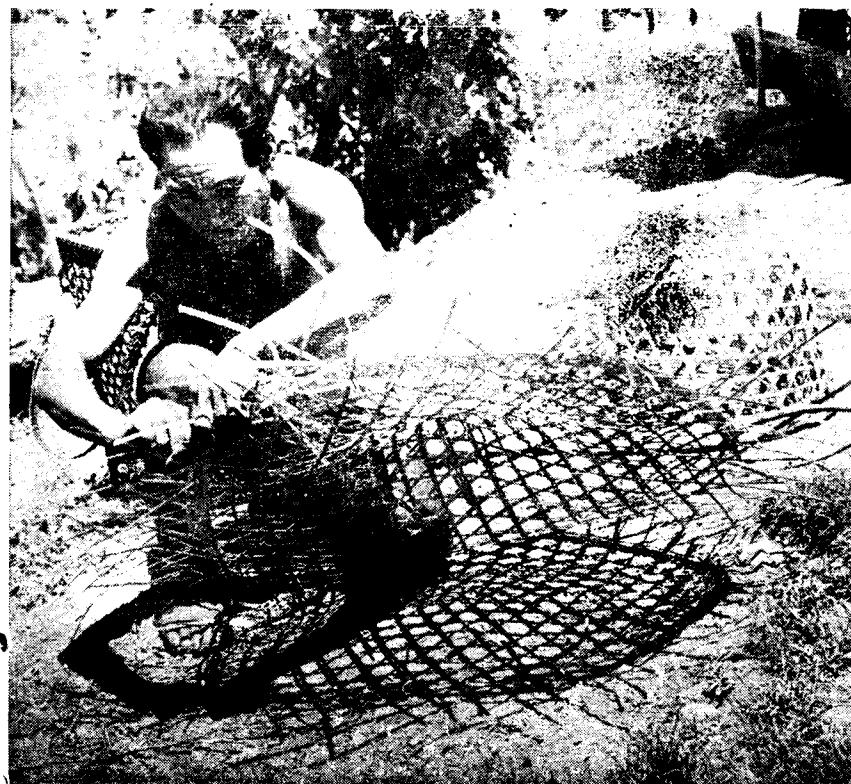




कबायली स्त्रियाँ पूर्वी धोव्र में पुराने किस्म का करघा इस्तेमाल करती हैं जिससे वे अपने खाली समय में अपने पहनने-ओढ़ने के कपड़े बुनती हैं। इससे बुना हुआ कपड़ा बड़ा साफ-सुथरा और रंगीन होता है। चित्र में नागा स्त्री अपने घर में कपड़ा बुनती हुई।



नागा कवायली क्षेत्र में बांस की टोकरी, छतरी तथा बांस की अन्यान्य वस्तुएं बनाने का बड़ा प्रचलन है। चित्र में बांस की कारीगरी का नमूना देखा जा सकता है।

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22

श्रावण 1899

इस अंक में

अंक 10
पृष्ठ संख्या

ग्राम विकास की राशि में 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी

2

— श्री सुरजीत सिंह बरनाला

4

केन्द्रीय बजट में ग्राम विकास को प्राथमिकता

— डा० शिवेन्द्र मोहन अध्यावाल

6

भूमि तथा जल स्रोतों का उपयोग

— श्री आई० जे० नायडू

8

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

9

अन्न उत्पादन और खाद्य स्थिति में सुधार

10

बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम

11

सहकारी प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि

12

ग्रामीण विकास : नई व्यूह रचना

14

— एच० आर० बिजारनिया

16

हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति के कीर्तिमान

— रघुनन्दन प्रसाद शर्मा

17

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी

— धर्मेन्द्र पाल सिंह

18

मणिपुर बने महान, भरे खेत खलिहान

— श्री एन० भट्टाचार्य

19

कुछ अनोखी मछलियां

— अरुण कुमार सिंह

20

कांगड़ा के लोक गीतों में सैनिक पत्नी की विरह वेदना

— मनोहर लाल

21

काली छाया (रूपक)

— डा० कृष्ण मुरारी शर्मा 'उन्निद्र'

22

भार (कहानी)

— सविता राण पुरा

23

केन्द्र के समाचार

24

साहित्य-समीक्षा

25

सम्पादकीय पत्र-व्यबहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, दिल्ली के पाते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुप

सम्पादक :

उपसम्पादक :

आवरण पृष्ठ :

महेन्द्रपाल सिंह

पारसनाथ तिथारी

शशि चावला

बार० सारंगन

सम्पादकीय

तीस वर्ष के अपने शासन काल में कांग्रेस सरकारें बीमारी,

बेरोजगारी और भुखमरी दूर करने की हमेशा ही कसमें खाती रहीं परन्तु इन तीनों का कलेवर लगातार बढ़ता रहा। अब जनता सरकार के हाथों सत्ता आई है और उसने भी इस समस्या से जूझने का फैसला किया है। आर्थिक क्षेत्र में नया दृष्टि कोण अपनाया जा रहा है और नयी आर्थिक नीति के निर्वाण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नई दिल्ली में योजना आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने नए दृष्टि कोण से नियोजन करने पर बल दिया है और बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख है। हो सकता है कि बेरोजगारों की संख्या इससे भी अधिक हो, पर जो भी हो, समस्या बड़ी जटिल है और यह तभी हल हो सकती है जब समस्या का सही निदान खोजा जाए। कांग्रेस सरकारों ने बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर देकर देश में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगों का काफी विस्तार किया परन्तु यह नीति बड़ी गलत सावित हुई और इससे समृद्ध वर्ग ही अधिक समृद्ध हुआ और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। यही हालत कृषि क्षेत्र में भी रही। सरकार की ओर से जो साधन-सुविधाएं कृषि के लिए उपलब्ध की गई वे भी बड़े किसानों के हाथों पड़ी और बेचारा छोटा किसान देखता ही रह गया। कहने का अर्थ यह है कि अब तक की हमारी आर्थिक नीति ही दोषपूर्ण रही है और इस नीति के परिणामस्वरूप अमीर अधिक अमीर होता गया और गरीब अधिक गरीब होता गया। परन्तु अब जनता सरकार की नीति ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी पर तीव्र प्रहार करने की है।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज ने स्पष्ट शब्दों में कहा

है कि हम बड़े उद्योगों को बनाए तो रखना चाहते हैं पर हमारा विशेष जोर ग्रामीण उद्योगों पर ही रहेगा क्योंकि एक लाख ६० की पूंजी लगाने पर बड़े उद्योगों में केवल चार व्यक्तियों को, छोटे उद्योगों में २० व्यक्तियों को और ग्रामीण उद्योगों में ६० व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही श्री फर्नांडीज ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को यह चेतावनी दे दी है कि उनकी मनमानी नहीं चलने वी जाएगी और यदि उन्होंने नई उद्योग नीति के कार्यान्वयन में रुकावटें ढाली तो उन्हें आडे हाथों लिया जाएगा परन्तु एक बात, जिसकी ओर हम उद्योग मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वह यह है कि ग्रामोद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे आधुनिक तरीकों से उत्पादन करने वाले उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। अतः जरूरी है कि उत्पादन के लिए कुछ उद्योग सुरक्षित रखे जाएं। इससे बात यह है कि ग्रामोद्योगों के तैयार माल की बिक्री की समुचित व्यवस्था का होना बड़ा जरूरी है और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि हमारे जनता पार्टी के न्यायिक विद्यालयों द्वारा सौच रहे हैं जैसे ग्रामीण लोगों में जाने के लिए उपलब्ध

स्कॉल और कालेजों से निकल कर प्रति वर्ष हजारों लाखों रुपये।

युवक काम-दिलाऊ केन्द्रों के चक्रकर काटते रहते हैं और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। यह समस्या अब हल हो सकती है जबकि हमारे जनता पार्टी के न्यायिक विद्यालयों द्वारा सौच रहे हैं जैसे ग्रामीण लोगों में जाने के लिए उपलब्ध

ग्राम्य विकास की राशि में 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी * श्री सुरजीत सिंह बरनाला

राष्ट्रीय जीवन में कृषि की प्रमुख भूमिका को देखते हुए 1977-78 वर्ष के लिए कृषि और सम्बद्ध सेवाओं जैसे कि सहकारिता, उंचरक, सिचाई, बाड़ि-नियन्त्रण तथा कृषि के लिए विजली के बास्ते परिव्यय बढ़ाकर 3,024 करोड़ ₹ ८० कर दिया गया है जबकि 1976-77 में यह 2,312 करोड़ ₹ ८० था। ग्राम्य विकास के लिए नियत धन राशि में 79 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ग्राम्य बिद्युतीकरण पर 56 प्रतिशत और प्रमुख तथा मझोली सिचाई पर 45 प्रतिशत राशि की वृद्धि की गई है। हमारी प्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर ऊँची हो। स्वतंत्रता के बाद कृषि में पैदावार निःसंदेह हुई है परन्तु यह वृद्धि अनेक वस्तुओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही। खाद्य और कृषि उत्पादन मौसम की दया पर निर्भर है। आगामी वर्षों में हमारा उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण फसलों में वृद्धि की दर तेज करना और कृषि उत्पादन पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करना होगा।

अनाज में गेहूं की एक मात्र ऐसी फसल है जिसके संबंध में हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति हुई है। हालांकि देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनाज चावल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, पर उसके परिणाम गेहूं के क्षेत्र में हुई प्रगति की बराबरी नहीं कर सकते। चावल की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न परिस्थितियों में होती है। हमने अधिक उत्पादन के मार्ग में उत्पन्न प्रमुख वाधाओं का पता लगाने और उपयुक्त समाधान ढूँढ़ने का प्रयत्न किया है। ज्वार के बारे में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का क्षेत्र बढ़ाने और कीड़ों

बथा वीमारियों की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। मकई की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पादक जिलों में संगठित प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही, ज्वार, बाजरा और मकई की रोग-रोधक, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को तैयार करने के लिए अनुसंधान प्रयत्न किए जा रहे हैं। दालों, तिलहनों और कपास के उत्पादन की समस्याओं पर विचार करने के लिए हाल में एक विशेष अन्तर-विभागीय दल बनाया गया था। इस दल ने इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन सुझाव दिए हैं। हमने इन सुझावों के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि सुलभ करने का निश्चय किया है, ताकि बढ़िया और प्रमाणित बीज तैयार करा कर वाजिब दामों पर किसानों को देवे जा सकें। फसलों में रोगों की रोकथाम के लिए विमानों से दवाई छिड़कने के कामों में सरकारी सहायता देने का निश्चय किया गया है। छोटे और सीमान्त किसानों को कपास, मूँगफली और सरसों की फसल पर विमानों से छिड़काव के लिए लागत का 100 प्रतिशत सहायता के रूप में मिलेगा और अन्य किसानों को 70 प्रतिशत। दालों और मूँगफली की अधिकाधिक फसल उगाने के लिए चुने हुए जिलों में विशेष अभियान शुरू करने का निश्चय किया गया है। पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं।

कृषि उत्पादन के लिए एक अत्यन्त बुनियादी आवश्यकता पानी की है। सिचाई को उच्च प्राथमिकता देना जनता सरकार की बुनियादी नीति का एक अंग है। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि जो परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं,

वे जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाएं। पानी के बारे में अन्तर-राज्यीय मतभेदों और विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जाएंगे। यथें बांध को जल्दी पूरा करने के लिए मैं सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्री की एक बैठक कराऊँगा ताकि इस बांध के सम्बन्ध में सभी मसले निपटा दिए जाएं। हमारी पुरानी सिचाई प्रणाली आधुनिक कृषि की आवश्यकता के अनुरूप सिद्ध नहीं हो सकती है। इस प्रणाली में सुधार की काफी गुजाइश है। भूमिगत जल और भूतल जल के उपयोग के महत्व को समझा जाना चाहिए और जहां भी संभव हो सके, भूतल जल साधनों को बढ़ाने के लिए उत्थले और गहरे दोनों प्रकार के नलकूप लगाए जाने चाहिए। बाढ़ की समस्या पर गहराई से विचार करने और बाढ़ नियन्त्रण तथा प्रबन्ध के बारे में ठोस सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बनाया जा चुका है। बाढ़ की समस्या को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसे जल साधनों के बहु-उद्देश्यीय विकास का अंग माना जाना चाहिए ताकि नदियाँ विनाश की लहर लाने के बजाय लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाएं। पिछले तीस वर्षों में हमारी सिचाई सुविधाओं में द्रुग्रन्थी वृद्धि हो गई है, फिर भी काफी कुछ करना बाकी है। हमें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वर्तमान क्षमता को बढ़ाना होगा। सरकार छोटी सिचाई योजनाओं को विशेष कर भूमिगत जल के विकास को महत्व देती है। इन पर अधिक से अधिक अमल करने के लिए प्रयत्न तेज किए जा रहे हैं।

हाल में विकसित उपयुक्त टैक्नो-लाजी की सहायता से 64,000 हैक्टेयर ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। पांचवीं योजना के दौरान

इस काम पर 7 करोड़ 80 खर्च किए जाएंगे। असिचित और सिचित क्षेत्रों के किसानों की आमदनी में अन्तर को कम करने और उत्पादकता के बीच की खाई को पाठने के लिए भारत सरकार ने शुष्क भूमि खेती कार्यक्रम शुरू किया है। 12 राज्यों में 24 मार्गदर्शी परियोजनाओं पर इस सम्बन्ध में काम हो रहा है।

एक स्थान पर ठीक समय पर ठीक मूल्य पर बढ़िया किस्म के बीज सुलभ कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक भी एक महत्वपूर्ण चीज है। पहले उर्वरकों की कमी की शिकायतें थीं पर व्यवस्थित प्रयत्नों से इस समस्या का

हल निकाल लिया गया है। उनके भावों की समीक्षा की जाएगी पर वर्तमान खंडीफ मौसम में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। भूमि सुधारों पर उचित प्रकार से और तेजी से अमल करना प्रमुख काम होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अतुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए चकवंदी एक महत्वपूर्ण कदम है। मत्स्य विकास के लिए वर्तमान वर्ष में परिव्यय में तीन गुना वृद्धि का प्रस्ताव है। इस काम को बढ़ाने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। समुद्र तट के आसपास मत्स्य साधनों का पता लगाने के लिए

कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के अंदरूनी भाग में भी मत्स्य विकास के लिए किशोर जोर दिया जा रहा है। मुर्गीपालन का ग्राम्य विकास में महत्व सरकार स्वीकार करती है। छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की मुर्गीपालन से आमदनी बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। वनों की ग्राम और आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वनों के बारे में राष्ट्रीय नीति में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

[लोकसभा में दिए गए भाषण
पर आधारित]

‘कुरुक्षेत्र’ के बारे में पाठक का पत्र

‘कुरुक्षेत्र’ का जून अंक देखा। मुख्य पृष्ठ ने इतना आकृषित किया कि पढ़े बिना न रह सका। लेख, कहानी, कविताओं का श्रेष्ठ चयन एवं यथास्थान देने के लिए सम्पादकगण बधाई के पात्र हैं।

पृष्ठ दो पर स्वास्थ्य मंत्री का लेख अत्यन्त ज्ञानवर्धक है। पत्रिका ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर है, इस बात की जलक प्रत्येक रचना में दीख पड़ती है। लघु उद्योगों के विकास में भारी उद्योगों की भूमिका, ‘सहकारिता में विपणन जग-शक्ति का नियोजन एवं विकास’, ‘लघु उद्योगों का निर्यात में योगदान’ आदि लेख इस बात को स्पष्ट करने में सहायक है।

दिलीप सिंह चौहान की कहानी ‘आशा’ अन्त तक पाठक की जिज्ञासा बढ़ाने में सक्षम है। कहानी में अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य एवं वार्तानुकूल भाषा ने कहानी को अत्यंत उत्कृष्ट बना दिया है।

जहां तक कविताओं का प्रश्न है, वहां उल्लेखनीय कविताओं में, ‘मरुस्थलों में कलियां खिला रहे हम,’ ‘हाथों की पूंजी’ प्रत्येक क्यारी लहलहायेगी, का नाम लिया जा सकता है। ग्राम्य वर्ग के अतिरिक्त पत्रिका सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आंशिक रूप से करती है। इसके लिए साहित्य समीक्षा का स्तम्भ, पहला सुख निरोगी काया का स्तम्भ पर्याप्त है। केन्द्र एवं राज्यों के समाचारों से ग्राम्यजनों को अवगत कराने में पत्रिका ने अलग-अलग स्तम्भ निश्चित करके एक सराहनीय कार्य किया है।

रजनी पाठक
—साहित्य-निकेतन
दावांग, 243638

कुरुक्षेत्र : अगस्त 1977

चलो गोरी गऊवां की ओर

॥१३॥

चलो, गोरी गऊवां की ओर,
नाच रहा सावन का मोर।

माटी गीत गाती है।
नदी इठलाती है॥।

लहरें चुनरियां तोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर।

हरा भरा नंदन है।
गंध भरा चंदन है॥।

बरसे बदरिया घोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर।

लगा हल पताल है।
मिट चला काल है॥।

चमके बिजुरिया जोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर।

बरगद की छांव है।
भू का स्वर्ग, गांव है॥।

मानो कहनवां, सखी मोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर।

॥१४॥

बनवारी लाल

—साहित्य-निकेतन

दावांग, 243638

कुरुक्षेत्र : अगस्त 1977

वार्षिक बजट सरकार की आर्थिक व सामाजिक धारणाओं का वर्णन है। बजट में की गई घोषणाओं से यह आभास हो जाता है कि सरकार देश की आर्थिक व सामाजिक नीतियों को किस दिशा में मोड़ देकर समाज की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान करना चाहती है। जनता सरकार के सामने कीमत वृद्धि, मुद्रा प्रसार, वेकारी, आर्थिक विकास की धीमी दर आदि समस्याएं मुँह फाड़े खड़ी हैं, जिनका समाधान करने के लिए ठोस उपायों वाली योजना बनानी होगी। इन सब तत्वों को ध्यान में रखकर सरकार ने जनता को बजट में अनेक उपहार देने का प्रयत्न किया है।

बजट में उद्देश्य यह रखा गया है कि उत्पादन तथा रोजगार की वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की प्रेरणा मिले और इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक प्रगति के फल भी जहां तक संभव हो, ज्यादा से

व्यवस्था की गई है जो केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के आयोजनों के समूचे परिव्यय का 30.4 प्रतिशत है। आयोजन की प्राथमिकताओं में इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित रूप से उत्साह वर्द्धक सिद्ध होगा। इस वर्ष योजना व्यय में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। गत वर्ष की योजना 7852 करोड़ ₹० की थी परन्तु 1977-78 में वह बढ़ाकर 9970 करोड़ ₹० कर दी गई है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की जरूरत को ध्यान में रखकर सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों को अधिक्रम योजना सहायता के रूप में देने को 100 करोड़ ₹० की, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए 260 करोड़ ₹० की और पम्प सेटों को विजली देने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई है। गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए वर्तमान व्यवस्था के अलावा 40 करोड़ ₹० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार विजली के लिए दोनों क्षेत्रों को सहयोगी के रूप में स्वीकार करना होगा। योजना व्यय में वृद्धि : कृषि और सहायक सेवाओं, बड़ी, मध्यम एवं छोटी सिंचाई की परियोजनाओं तथा उर्वरकों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवस्था एवं ग्रामीण इलाकों के लिए निर्धारित विजली के क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर 3028 के करोड़ रुपये के आयोजन परिव्यय की

ही हल नहीं हो सकती। अपर्याप्त वृद्धि की दर के कारण और उद्योग में पूँजी की की प्रधानता बढ़ जाने के कारण भारत के औद्योगिक ढांचे में रोजगार के अवसरों का काफी तेजी से विस्तार करने की क्षमता नहीं रही है। अतः इस बजट में कृषि विकास के साथ-साथ गांवों में औद्योगिक उपकरणों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। कम्पनियों को ग्राम कल्याण और ग्रामोत्थान के कामों में हाथ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन न देने के लिए इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि इन कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर खर्च किए गए खर्च की, उनके कर योग्य लाभों का हिसाब-न्लगाते समय कटौती कर दी जाएगी। देहाती इलाकों में छोटे पैमाने के औद्योगिक उपकरणों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रेरणास्वरूप ऐसे उपकरणों को, जो 30 जून, 1977 के बाद शुरू किए गए हैं, दस वर्षों तक कर योग्य लाभों का हिसाब लगाने में

केन्द्रीय बजट में ग्राम-विकास को प्राथमिकता

★ डा० शिवेन्द्र मोहन अग्रवाल

ज्यादा व्यक्तियों को प्राप्त हों। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कृषि, लघु ग्रामोद्योगों एवं आधार भूत ग्रामीण ढांचे की पूँजी निवेश पर वल दिया गया है। भारत ग्राम एवं कृषि प्रधान देश होने के कारण बजट में कृषि विकास को प्राथमिकता दी जाए तो आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। परन्तु इस बजट में जहां तक एक ओर कृषि को प्रधानता दी गई, वहां दूसरी ओर आधुनिक उद्योगों के प्रति उदासीनता के अनुभवों से यह सीख मिल गई है कि आर्थिक विकास की गति को तेज बनाने के लिए दोनों क्षेत्रों को सहयोगी के रूप में स्वीकार करना होगा। योजना व्यय में वृद्धि : कृषि और सहायक सेवाओं, बड़ी, मध्यम एवं छोटी सिंचाई की परियोजनाओं तथा उर्वरकों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवस्था एवं ग्रामीण इलाकों के लिए निर्धारित विजली के क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर 3028 के

है। इस प्रकार विजली के विकास के लिए जो कृषि और उद्योग दोनों के लिए अपरिहर्य है, 234 करोड़ ₹० की राशि रखी गई है। तेल के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल की खोज तथा निष्कासन कार्यक्रमों के लिए गत वर्ष के 485 करोड़ ₹० की तुलना में इस वर्ष 677 करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई है और कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य भी गत वर्ष के 88.9 लाख टन से बढ़ाकर 13.1 लाख टन कर दिया है। पानी पंप करने वाले पावर पंपों पर लगने वाले शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके पावर टिलरों को सामान्य उत्पादक शुल्क से मुक्त रखकर छोटे किसानों की सहायता की गई है।

करों में छूट : बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक दबाव डालने वाली समस्या है। अतः इसके हल के लिए सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यह समस्या केवल औद्योगिकरण मात्र से

अपने लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर कटौती का लाभ मिलेगा। श्रम प्रधान उद्योग : रोजगार के अवसरों को बढ़ाने वाले उद्योगों को इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि यदि खादी एवं ग्राम उद्योगों को सही दिशा में विकसित किया जाए तो वे बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधाओं का विस्तार करेंगे। योजना में इनके विकास के लिए 35 करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई है, साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि आवश्यकता पड़ने पर और अधिक धन राशि की प्राप्ति हो सके। ऐसा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से लगभग 25 लाख लोगों को जीवन यापन की मुविधा मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त, हथकरघा के विकास के लिए 20 करोड़ ₹० और 4 करोड़ ₹० रेशम के कीड़े पालन-उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन

मिलेगा। सरकार ने उत्पादक शुल्क घटाने या कम करने की जो घोषणा की है उसका लाभ हैडलूम उद्योग को भी मिला है। अब तक सीधी रील हैंकों में सप्लाई किया गया काटन यार्न ही उत्पादन शुल्क से मुक्त था। अब क्रोस रील हैंकों में 20 एस० काउन्ट तक के कोटन यार्न को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया है।

एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कृषि एवं उद्योग का विकास परिवहन व संचार साधनों के समुचित विकास पर ही निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैलगाड़ी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। अतः इसकी उपयोगिता को अधिक सक्षम बनाने के बारे में सोचना शुरू किया जाना

चाहिए। पश्चिमी तकनीक की अन्धा-धुन्ध नकल करने के बजाय देशी तकलीक और उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि की वृद्धि तेजी से होने से मरम्मत सेवा, परिवहन आदि सहायक कार्यकलापों में रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास पर खास तौर से ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि की उपज की विक्री के लिए उचित व्यवस्था करना दुष्कर होगा यदि निकटतम मंडियों के साथ हमारे गांव को जोड़ने के लिए सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी। इस बजट में ग्रामीण सड़कों के विकास के

लिए 20 करोड़ 80 की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों व तार धरों को अधिक सुविधाएं जूटाने के लिए एक करोड़ 80 की व्यवस्था की गई है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्राम विकास हेतु यह बजट जनता सरकार के संयम और विवेक का सूचक है। यह आशा की जा सकती है कि यह बजट गांधीजी के आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के विचार को ठोस रूप देने में आधारशिला का कार्य करेगा।

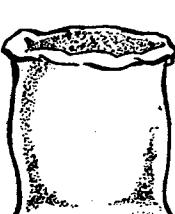
एच 9, नवीन शाहदरा,
दिल्ली-110032

विश्वसनीय एवं असली पन्तनगर बीज खरीदते समय कृपया निम्न तथ्यों को अवश्य देखें

- बीज सही प्रकार के थैलों में है, जिस पर
 1. सील 2. प्रमाणी करण टैग तथा
 3. दो बाली एक चक्र का निशान है।



असली बीज ही
सरीदे



नकली बीज न
सरीदे

- कि थैलों पर हमारे निगम का निशान दो बाली और चक्र देखें।



उत्तम बीजों की पहचान
दो बाली एक चक्र निशान

- कि आप हमारे अधिकृत वितरक एवं विक्रेताओं से, जिनके पास तराई विकास निगम का साइनबोर्ड व प्रमाण पत्र है, बीज प्राप्त कर रहे हैं।



केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही सरीदे।
अधिक दाम न दें, गलत स्थान से बीज न सरीदे,

पन्तनगर के बढ़िया बीज सही समय पर
निर्धारित कीमत से सरीदे और ज्यादा लाम कमायें।

अधिक जानकारी के लिये कृपया संपर्क करें अथवा लिखें :—
मिनेजिंग डाइरेक्टर
तराई खेलपर्मेट कार्पोरेशन लि०
पन्तनगर, पौ०आ० हल्दी, जिला नेमीताल

IMPACT

भूमि तथा जल स्वोतों का उपयोग

लिखने वाले श्री आई० जे० नायडू

कृषि-क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य साधनों में भूमि तथा जल उपयोग का प्रमुख स्थान है। अपने देश में अनेक बड़े भागों में पानी की बहुतायत नहीं है और साथ ही भूमि में भी उसके अत्यधिक प्रयोग के कारण उर्वरता में कमी आई है। पहले जिन क्षेत्रों में किसी समय जंगल थे और भूमि हरियाली से ढकी हुई थीं, वे अब नंगे तथा अनुपजाऊ हो चले हैं अथवा वे ही स्थान अब ऐसे हो गए हैं जिनका तात्कालिक लाभ की दृष्टि से प्रयोग संभव नहीं है। परिणाम यह हुआ कि अनियमित रूप से भूमि के अत्यधिक प्रयोग के कारण काफी भूमि कमज़ोर होने लगी जिससे जमीन कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गई। यह समस्या मूला वाले इलाकों में और भी विकट है। जन-संख्या की वृद्धि के कारण उन जमीनों की भी खुदाई तथा जोताई की जाने लगी, जिन पर हमेशा ही हरियाली रहनी चाहिए थी। यह समस्या तब और विकट हो जाती है जबकि पशुओं के झुण्ड के झुण्ड ऐसे क्षेत्रों में चरने लगते हैं जहां उन्हें चरने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एक ही भू-भाग पर मानव तथा पशु दोनों के बीच अपने जीवन के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है।

मूला पड़ने वाले क्षेत्रों में पानी एक दुर्लभ पदार्थ है। कुछ स्थानों में वर्षा जल का उपयोग अच्छी तरह नहीं हो पाता क्योंकि ऐसे स्थानों की जमीनें पर्याप्त नमी को सोखने में असमर्थ होती हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त एक अन्य बात है। वह यह कि वर्षा क्रतु में काफी कुछ पानी तो थोड़े दिनों के भीतर वरस जाता है, जो अनियमित रूप में वह जाता है और साथ ही जमीनों के कीमती ऊपरी भाग को भी बहाल ले जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूमि की रक्षा न की जाए तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10 टन मिट्री वह जाती है और 10 टन मिट्री कई वर्षों में जाकर फिर जम पाती है। अतः समस्या बड़ी भारी है। इस बात को ही ध्यान में रखने हुए काफी कुछ विचार इस सन्दर्भ में इन क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया है। इस सन्दर्भ में जल संग्रह क्षेत्र को सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीका माना गया है, जिससे अनियन्त्रित भूमि-क्षय तथा अत्यधिक जल-बहाव को रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में मानव अधिकतम उत्पादन के लिए भूमि तथा जल का प्रयोग कर सकता है।

जल संग्रह क्षेत्र की योजना : दूसरे शब्दों में इसे जलग्रहण क्षेत्र भी कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का ऐसा भूमिक्षेत्र है, जहां से किसी निश्चित स्थान का पानी नालियों में बहता रहता है। कोई भी जल संग्रह क्षेत्र समतल हो सकता है या इसकी परिधि में पहाड़ या पहाड़ियां भी हो सकती हैं। जल संग्रह क्षेत्र

किसी मकान या खेत के पिछले भाग में भी बनाया जा सकता है। हजारों किलोमीटर में निर्मित एक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र भी हो सकता है। मुख्य नदी जल क्षेत्र के साथ-साथ कुछ सौ हेक्टेयर भूमि में अनेक जल संग्रह क्षेत्र हो सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है: पानी की प्रत्येक बूँद जो आकाश से गिरती है, वह या तो जमीन के अन्दर प्रवेश कर जाती है और या किसी दिशा में लुढ़क जाती है। इसी तरह कुछ बूँदें जो जमीन पर गिरती हैं, वे खास दिशा की ओर लुढ़कती जाती हैं और धरातल के ढलान द्वारा बहती जाती हैं। अन्त में जाकर वे सारी बूँदें एक बहुत ही छोटे स्थान में एकत्रित होकर धारा का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार—जल संग्रह क्षेत्र वह स्थान है जहां पानी गिरता है और वह स्थान जहां यह इकट्ठा होकर विभिन्न दिशाओं में गतिमान होता है। किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति तथा भूमि तथा जल को ध्यान में रख कर जल संग्रह क्षेत्र का विस्तार निश्चित किया जा सकता है। एक किसान को ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि वह अपनी जमीन पर ही पानी की प्रत्येक बूँद रोक ले। उसके लिए ऐसा करना संभव हो सकता है और यह भी संभव है कि बहुत से किसान उपलब्ध वर्षा जल तथा भूमि-क्षय पर तकनीकी इंजीनियरी कार्यशाला के माध्यम से नियन्त्रण करने के लिए प्रयास करें। बड़े-बड़े बांध भी पाये जाते हैं जिनको भरने के लिए अत्यधिक जल-प्रवाह की आवश्यकता होती है। बांध तथा जलाशय बनने पर ही पानी पर नियन्त्रण किया जा सकता है। यदि इस प्रकार नियन्त्रण कार्य नहीं होगा, तो नदियां पहले की तरह ही अपना मार्ग बदलती रहेंगी और धन सम्पत्ति को उसी प्रकार नष्ट करती रहेंगी जैसा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखा जाता है।

पानी का नियन्त्रित प्रयोग : चूंकि वर्षा वाले इलाकों में डी. पी. ए. पी. एक कार्यक्रम चालू है, अतः पानी का नियन्त्रण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए खासतौर से इन क्षेत्रों में—जल संग्रह क्षेत्र कृषि विकास का मूल आधार बन गया है। विकास का कोई भी क्षेत्र हो, उसकी योजना आंशिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर होनी चाहिए। योजना बनाने वाले को नियन्त्रित करना होता है कि आंशिक आत्म नियन्त्रित तथा प्रशासनिक संभावना का मेल है या नहीं। अतः हमने इस बात का सुझाव दिया है कि खासतौर से पानी और भूमि-कटाव के नियन्त्रण वाले क्षेत्र में विकास के लिए लगभग 5,000 हेक्टेयर वाले जल संग्रह क्षेत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। पांच हजार हेक्टेयर का मतलब यह होगा कि इसकी परिधि में आठ से दस गांव आएंगे और इस प्रकार का क्षेत्र बहुत अच्छी तरह आंशिक आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत आ सकते हैं। वाटरशेड (जल संग्रह क्षेत्र) का विकास एक जटिल कार्य है। इसके सारे क्षेत्र के धरातल ढलान, भूमि-प्रयोग तथा भूमि क्षमता आदि का नक्शा तैयार करने की जरूरत होती है। यदि एक बार सारे क्षेत्र

का नक्शा तैयार कर लिया जाता है तो उन स्थानों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है जहां पानी को नियन्त्रित किया जा सकता है और इस प्रकार के पानी के नियन्त्रण के लिए छोटी-छोटी सिचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस सन्दर्भ में छोटे-छोटे नियन्त्रण बांध भी हो सकते हैं जो पानी के वहाव को नियन्त्रित कर सकेंगे। इसी तरह उन क्षेत्रों का भी पता चल जाएगा जहां भूमि की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनसे आर्थिक दृष्टि से कोई भी लाभप्रद फसल पैदा नहीं की जा सकती। अतः यह अधिक उपयोगी होगा कि ऐसे क्षेत्रों को हमेशा हरित पट्टी के रूप में ही रखा जाए। इस प्रकार की हरित पट्टी धास हो सकती है या ईंधन की लकड़ी या चारे वाले पेड़ हो सकते हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कृषि-विकास के लिए जल संग्रह क्षेत्र की योजना एक बहुदेशीय योजना है।

आधारभूत ढांचे के विकास में धन की आवश्यता होती है। इसलिए इन विनियोगों से होने वाले लाभ ऐसे होने चाहिए जिससे देनदारी की व्यवस्था होती रहे। जल के नियन्त्रण से अनाज का अधिक उत्पादन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि फसलों के लिए एक उपयुक्त लाभप्रद तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि भूमि रक्षण इंजीनियरों तथा कृषि-विकास कार्यकर्ताओं के कार्यों में ताल मेल हो। इसी तरह यदि जमीनें फसल उगाने के योग्य नहीं हैं, तो इसे या तो चरागाह के रूप में बदल देना चाहिए या इस पर वृक्ष लगा देने चाहिए। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठेगा कि ऐसे चरागाहों का प्रयोग कौन करेगा और ऐसे चरागाह किस प्रकार के पशुओं के लिए होंगे? अतः पशु देख-भाल विभागों को परीक्षण करना होगा कि किस प्रकार के पशु इन जमीनों में उगे हुए चरागाहों पर चर कर जीवित रह सकेंगे। इसलिए इस विभाग का संबंध फसल उगाने से भी है क्योंकि ये सीमान्त जमीनें व्यतिगत भी हो सकती हैं। इसी प्रकार यह भी संभव है कि उन इलाकों में जहां वृक्ष उगाये जा सकते हैं, वन-विभाग भी इस कार्य में शरीक हों। वन-विभाग को तब सोचना पड़ेगा कि उद्योगों में काम आने वाले वृक्षों को उगाना चाहिए या थोड़े समय में समाज को लाभ पहुंचाने वाले वृक्षों को उगाने में पहल करनी चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विकास के लिए एक बहुत ही सतर्कतापूर्ण तथा समन्वित योजना की आवश्यकता है। चाहे कभी एक वस्तु की भी क्यों न हो, इससे उपलब्ध भूमि तथा जल के पूर्ण एवं स्थायी प्रयोग में कमी रह जाएगी।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण : प्रशिक्षण तथा अनुसंधान महत्वपूर्ण अवयव हैं। हम लगातार कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते रहे हैं, ताकि जल संग्रह क्षेत्र योजना के महत्व पर राज्य स्तर के कर्मचारियों से लेकर क्षेत्रों में काम करने वाले सभी सरकारी कार्मचारियों को जानकारी दी जा सके और इनके साथ-साथ जल संग्रह क्षेत्र के प्रबन्ध संबंधी सभी पहलुओं पर जोर देते रहे हैं। अनेक प्रबन्धकारी संस्थान प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से इन जल संग्रह क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

एक उचित प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा विकसित किया जा सके। जैसा कि देखा जाता है कि हमने जिला तथा जल संग्रह क्षेत्र के स्तर पर बहुदेशीय समन्वय सुनिश्चित करने का कठिन काम हाथ में ले रखा है। अनेक शाखाओं के प्रधानों के लिए सामान्य प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा चुकी है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न शाखाओं में परस्पर संबंध रहे ताकि जल संग्रह क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसी प्रकार राज्य स्तरों पर भी ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं के विषय में सावधान रहती हैं और उन्होंने अन्त विभागीय समन्वय समितियों की स्थापना भी की है तथा वे ऐसे कार्यक्रमों के सभी पहलुओं पर देख-भाल करती रहती हैं।

हम लोग अभी इस कठिन कार्य की शुरुआत में ही हैं। अभी तो इस दिशा में काफी कुछ करना शेष है। हमें आशा है कि न केवल सरकारी कार्यकर्ताओं में अपिनु ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाली जनता में भी शीघ्र ही पर्याप्त उत्साह पैदा होगा। जहां कहाँ भी विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं उनके सम्बन्ध में हमारा प्रयत्न यह रहा है कि मानव समुदाय इनमें भाग ले और उनकी स्वीकृति और सहमति से ही कार्यक्रम संचालित किए जाएं। इस आधार पर ही तकनीक का स्थानान्तरण प्रभावशाली ढंग से हो पायेगा। एक बार जब जनता तथा सरकारी कार्यकर्ता नये विचार स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करने में लग जाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा और साथ ही विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग साधारण लोगों के लाभ के लिए होने लगेगा।

अनु०-डा० लक्ष्मीनाराण पाठ्क०
ए-३३९, सूर्यनगर,
पो० आ० चिकम्बरपुर,
गाजियाबाद-२०१००६ (उ० प्र०)

**यावज्जीवनं भ्रियेत्
तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्**

योऽधिकमनुमन्येत्

सः स्तेनः दण्डमर्हति

जितने से जीवन चल सके, उतने पर ही इंसान का अधिकार है। जो इससे ज्यादा चाहता है, वह चोर है और सजा पाने योग्य है।

—श्री मद्भागवत

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

बुनियादी स्तर पर सुव्यवस्थित बहु-उद्देशीय संगठन के गठन के लिए महकारियों के पुनर्गठन को प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है। ग्रामीण क्रृष्ण ग्रस्ताता सम्बन्धी कानूनी उपायों के अलावा, बैकलिपक संस्थागत प्रवन्ध करने के लिए आनुषंगिक उपायों की विशेष समिति ने जांच की थी। यह जानकारी कृषि और सिचाई मंत्रालय के ग्रामीण विकास की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस विभाग के मध्ये कार्यक्रमों में मुख्य बल व्यापक ग्रामीण विकास के सम्पूर्ण ढांचे में कमज़ोर तथा गरीब ग्रामीणों की आर्थिक नग्ना सामाजिक स्थिति सुधारने पर दिया गया है। समन्वित ग्राम विकास का नया कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों के अधिकाधिक एकनीकरण तथा उपयोग द्वारा वेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी और देहाती गरीबी की समस्याओं को हल करने पर बन दिया जाता है। 18 राज्यों में 20 जिलों को चुना गया है जहां इस योजना को शुरू किया जाएगा।

आंचलिक प्रदेश और कर्नाटक को छोड़ कर सभी राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों द्वारा खंडों का प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा द्वितीय चरणोत्तर में वर्गीकरण करने की प्रणाली अपनाई गई है। आंचलिक प्रदेश में इनका वर्गीकरण पिछड़ा खंड, साधारण खंड और विकसित खंड के रूप में किया गया है।

कर्नाटक ने वर्गीकरण करना छोड़ दिया है और खंड के स्थान पर ताल्लुकों को सामुदायिक विकास यूनिट के रूप में

स्वीकार किया है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक विकास और पंचायती राज क्षेत्रों के अधीन वर्ष 1976-77 के लिए परिव्यय 1896.42 लाख रु० था जो वर्ष 1977-78 में बढ़ कर 2853.65 लाख रु० हो गया है।

उपलब्धियों के सामान्य मूल्यांकन से पता चलता है कि वर्ष 1975-76 में अधिकांश कार्यों में प्रशंसनीय प्रगति हुई है, किर भी कुछ मदों में थोड़ी सी कमी भी पाई गई है। खंड कृषि उपज को अधिक से अधिक बढ़ाने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के लिए उपाय करते रहे हैं। ग्राम सेवकों को अधिकांशतः कृषि कार्य सौंपे गए हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि कृषि उत्पादन के प्रभारी विस्तार कार्यकर्ताओं की पूरी संख्या बनाई रखी जाए और कार्यक्रमों के अनुसार, जहां आवश्यक हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए।

पशुपालन के क्षेत्र में 1974-75 की उपलब्धि के मुकाबले में 1975-76 में आमतौर पर सुधार हुआ है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी राष्ट्रीय परिपद् की सिफारिशों के अनुसार 20 जुलाई, 1974 को एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1976 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

कुछ राज्य सरकारों ने पंचायती राज प्रणाली का 'पुनर्विनोकन' करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। आंचलिक प्रदेश, विहार, महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान की सरकारों द्वारा नियुक्त की गई उच्चाधिकारी समितियों ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकारों को दे दी हैं।

उपभोग क्रृष्ण

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अच्छी वसूली, डिपाजिट एकत्रीकरण तथा अधिकाधिक अंशपूर्जी अंशदान द्वारा सहकारी समितियों के आंतरिक संसाधनों को मजबूत बनाने का कार्य भी आरम्भ किया गया है ताकि वे उपभोग क्रृष्ण की

आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बन सकें। भारतीय रिज़व बैंक ने उपभोग क्रृष्ण देने के लिए सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं। भारतीय रिज़व बैंक कृषि उत्पादन क्रृष्ण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतम क्रृष्ण सीमाएं स्वीकृत करता रहेगा। इस संदर्भ में पुनर्गठित समितियों की अंशपूर्जी अंशदान के लिए पावता सीमा प्रति सोसायटी 5,000 रु० बड़ा दी गई है। 'शुद्ध उपभोग क्रृष्ण' में शामिल संभाव्य जोखिम पूरा करने के लिए सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्य बैंकों के लिए जोखिम निधि अंशदान की एक नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों तथा केन्द्र द्वारा जोखिम निधि अंशदान की देयता बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

कृषि क्रृष्ण के क्षेत्र में 'वहु एजेंसी पहुंच' के अंतर्गत कृषि क्रृष्ण संस्थाओं के माध्यम से देने की नीति जारी रही। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बल संस्थागत कृषि क्रृष्ण की मात्रा को बढ़ाने, ग्राम स्तर पर समन्वित क्रृष्ण ढांचा सुलभ करके सेवा की दशा में सुधार करने पर है ताकि किसानों की आवश्यक क्रृष्ण दिया जा सके और उनके द्वारा अपेक्षित सेवाएं तथा सप्लाई सुलभ की जा सके और इनका अधिकाधिक भाग कृषि समुदाय के कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाया जा सके।

ग्रामीण बैंक

मार्च, 1977 तक 47 अंद्रेशीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। इनमें से 45 ने उस तारीख तक 13.09 करोड़ रु० के क्रृष्ण दिए और 10.25 करोड़ रु० के डिपाजिट जुटाए।

भूमि विकास बैंकों द्वारा क्रृष्ण देने की पावता की विधि में कुछेक परिवर्तन किए गए हैं।

सहकारी भूमि विकास सम्बन्धी समिति ने क्रृष्णदायी नीतियों तथा पद्धतियों के सुधार के लिए विस्तृत मुझाव दिए हैं। ये सुझाव भूमि विकास बैंकोंतथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं। *

अन्न उत्पादन और खाद्य स्थिति में सुधार

देश में 1976-77 के दौरान खाद्य स्थिति अमंतर पर अच्छी रही।

देश के सभी भागों के बाजारों में उचित मूल्यों पर खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध था। आलोच्य अवधि में अनाज की रिकार्ड वसूली हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की निकासी में गिरावट आई, सरकार के पास भण्डार में अत्यधिक वृद्धि हुई और अनाज का आयात बन्द कर दिया गया था। कृषि एवं सिचाई मंत्रालय, के खाद्य विभाग के 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 1975-76 में खाद्यान्नों का 1208 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन होने और सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सरकारी एजेंसियों द्वारा, वसूली मूल्यों पर विक्री के लिए अनाज की सारी मात्रा खरीदने के कारण 1975-76 की फसल से खाद्यान्नों की वसूली 132 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई थी। 1976-77 की फसल से वसूली की गति अच्छी चल रही है। बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धि बढ़ने के कारण 1976 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की निकासी 1975 के 113 लाख टन से गिरकर 92 लाख टन रह गई। खाद्यान्नों की रिकार्ड वसूली साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम निकासी होने के कारण स्टाक में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। सरकार के पास मार्च, 1977 के अन्त में कुल स्टाक 180 लाख टन था जब कि मार्च 1976 में यह स्टाक 105 लाख टन था। स्टाक में निरन्तर सुधार होने से सरकार ने जून 1976 में खाद्यान्नों का आगे आयात न करने का फैसला किया।

रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्नों का 180 लाख टन से भी ज्यादा स्टाक होने और देश भर में 240,000 से भी अधिक राशन/उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछा होने से देश में अब राष्ट्रीय खाद्य

सुरक्षा प्रणाली के दो अत्यधिक महत्व पूर्ण तत्व हैं, जिनकी चार बातें इस प्रकार हैं:-

1. सिंचित तथा वर्षा वाले क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार।
2. उत्पादन में अधिक स्थिरता लाना।
3. अनाज का पर्याप्त आरक्षित अर्थात् बफर स्टाक तैयार करना।
4. कुशल वितरण प्रणाली।

इस सुगम खाद्य स्थिति से बहुत नियन्त्रणों में या तो ढील दे दी गई या हटा लिए गए हैं जोकि कई वर्ष से चले आ रहे थे। दक्षिण और उत्तर में चावल के बड़े क्षेत्र बनाए गए हैं। गेहूं के पदार्थों के उत्पादन मूल्य, संचलन और वितरण पर लगे नियन्त्रण हटा लिए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। अप्रैल, 1977 से गेहूं के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध उठा लिए गए हैं।

उत्पादन के लिए, प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1975-76 के दौरान फसलों के लिए मौसम की स्थिति कुल मिलाकर अनुकूल थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आदान बिजली, सिचाई, उर्वरक की सप्लाई की स्थिति भी बेहतर थी। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1208.3 लाख टन हुआ, जबकि पिछले वर्ष 998.3 लाख टन (संशोधित अनुमान) हुआ था। उत्पादन में 210 लाख टन या 21% की वृद्धि हुई थी। 1975-76 में सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी लेकिन ज्वार की पैदावार में 8.5% की गिरावट आई थी। हाल ही के वर्षों में दालों की पैदावार स्थिर रही है, इस वर्ष दालों की पैदावार 131.3 लाख टन के रिकार्ड पर पहुंच गई जोकि पिछले वर्ष के आंकड़ों से 30% से भी ज्यादा थी। 1976-77 के दौरान खरीफ की

फसलों के लिए मौसम की स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल थी लेकिन पिछले वर्ष जैसी नहीं थी। मौसम की प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद 1976-77 के खरीफ खाद्यान्नों की पैदावार सामान्य स्तर के आस-पास होने की सम्भावना है यद्यपि 1975-76 के दौरान 741.9 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन होगा। रबी खाद्यान्नों की समूची संभावनाएं अच्छी दिखाई देती हैं यद्यपि 1977 में बेमौसम की वर्षा होने से खड़ी फसलों को कुछ क्षति पहुंचने की खबर है।

रिपोर्ट में कहा गया है 1975-76 के दौरान अनाजों का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण कुल वसूली लगभग 132 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 82 लाख टन खाद्यान वसूल किए गए थे। चावल की वसूली (चावल के हिसाब से धान समेत) 63.32 लाख टन हुई थी जबकि पिछले वर्ष मौसम में यह वसूली 37.95 लाख टन थी। 83.22 लाख टन की कुल मात्रा में लगभग 40.35 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में दिया गया था।

1976-77 में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल वसूल की गई मात्रा 66.02 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष गेहूं की कुल वसूली 40.49 लाख टन थी। केन्द्रीय पूल में 1976-77 में गेहूं की दी गई मात्रा 50.80 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष (1975-76) 35.72 लाख टन थी। इसके अलावा, 1976-77 के विषय मौसम के दौरान पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों के पास रही 13.14 लाख टन गेहूं की मात्रा भी केन्द्रीय पूल में आनी है।

1975-76 के विषय मौसम में मोटे अनाजों की वसूली 3.01 लाख टन हुई थी और केन्द्रीय पूल में मोटे अनाजों की दी गई मात्रा 0.27 लाख टन थी।

चालू खरीफ मौसम 1976-77 में लगभग 41.84 लाख टन खरीफ के अनाजों (चावल और मोटे अनाज) की वसूली 31 मार्च, 1977 तक हुई थी जिनमें से 26.94 लाख टन अनाज केन्द्रीय

पूल में दिया गया हैं।

आयात और निर्यात

1976 के दौरान भारत में कुल 65.15 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया था जबकि 1975 में 74.07 लाख टन किया गया और 1974 में 48.74 लाख टन खाद्यान्न आयात किए गए थे। जून 1976 में सरकार ने यह

निर्णय किया कि व्यापारिक खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जाए क्योंकि सरकार के पास उचित मात्रा में स्टाक जमा है।

1976 के दौरान लगभग 38.5 हजार टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था। इसके अलावा, 1976-77 के दौरान 40 हजार टन जौ और 5

हजार टन दालों का एक कोटा निर्यात के लिए निर्धारित किया गया था जबकि 1976 के अन्त तक 31.2 हजार टन जौ और 5.4 हजार टन दालें निर्यात की गई थीं। बाद में मूल्यों में बढ़ोत्तरी का दबाव पड़ने पर 1976-77 की अन्तिम तिमाही में दालों के निर्यात न करने का निश्चय किया गया था।



बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम

सामाजिक न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण के ही क्षेत्र में 1976-77 के दौरान कई कार्यक्रम आरम्भ किए गए। यह जानकारी समाज कल्याण विभाग की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। बच्चों के कल्याण के लिए समन्वित बाल कल्याण सेवाएं और विशेष पोषाहार कार्यक्रम शुरू किए गए। महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं को होस्टल सुविधा देने और उन्हें अपना काम चलाने के लिए आवश्यक शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। विकलांगों के पुनर्वास के लिए उन्हें छावन्वृत्तियां व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने के लिए रोजगार कार्यालय खोलने की विशेष योजनाएं शुरू की गईं।

स्वयंसेवी प्रयत्न को बढ़ावा देना और उस का विकास करना समाज कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका कारण यह है कि समाज कल्याण समस्याओं का आकार और प्रकार ऐसा होता है कि यह आवश्यक हो जाता है कि कल्याणकारी योजनाओं को कारगर रूप से तैयार करने तथा उन्हें कायदान्वित करने में लोग भाग लें। आरम्भ किए गए कार्यक्रमों के स्वरूप में जरूरी परिवर्तन किए गए हैं और निवारक तथा पुनर्वास सेवाओं पर अधिक बल दिया गया है। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय की क्षमताओं का विकास करना है ताकि अपनी कमजोरियों के बावजूद वे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में प्रवाहित हो सकें।

बाल कल्याण

1976-77 के दौरान बाल कल्याण और पोषाहार के विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। देवभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के कल्याण की योजनाओं के लिए पांचवीं योजना के प्रारम्भ में रखी गई 5 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ा कर 8 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 25,000 बच्चों को बाल कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पांचवीं योजना के प्रारम्भिक लक्ष्य में संशोधन किया गया। पहले 13000 बच्चों को यह लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। 1976-77 के दौरान 163 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में स्वीकृत की गई थी जिसमें 3905 अतिरिक्त बच्चों के भरण पोषण के लिए अनुदान शामिल है। इन बच्चों की कुल संख्या 19,810 तक बढ़ा दी गई है। 1975-76 में मंजूर की गई 33 प्रायोगिक समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं जारी रहीं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, तथा दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य पोषाहार तथा शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

महिला कल्याण कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्बन्ध में फरवरी 1976 में महिलाओं की भूमिका और अधिकारों के बारे में अनुमोदित राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय महिला समिति का गठन किया गया। इस प्रकार की समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है। 33 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना

क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए काम चलाऊ शिक्षा देने की योजना ने चालू वर्ष में तेजी से प्रगति की। सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक शिक्षा देने के लिए कक्षाएं चलाने वाले केन्द्रों की संख्या अब 2269 है तथा इन कक्षाओं में शिक्षा पाने वाली स्त्रियों की संख्या 40249 है। शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के भवन निर्माण की एक योजना शुरू की गई। इस स्कीम ने पांचवीं योजना में काफी प्रगति की और 1976-77 में 21 नए होस्टलों के निर्माण तथा विस्तार के लिए मंजूरी दी गई ताकि 1611 कामकाजी महिलाओं को रहने का स्थान मिल सके। 60 नगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास व्यवस्था करने के लिए पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में कुल स्वीकृत क्षमता 6655 है।

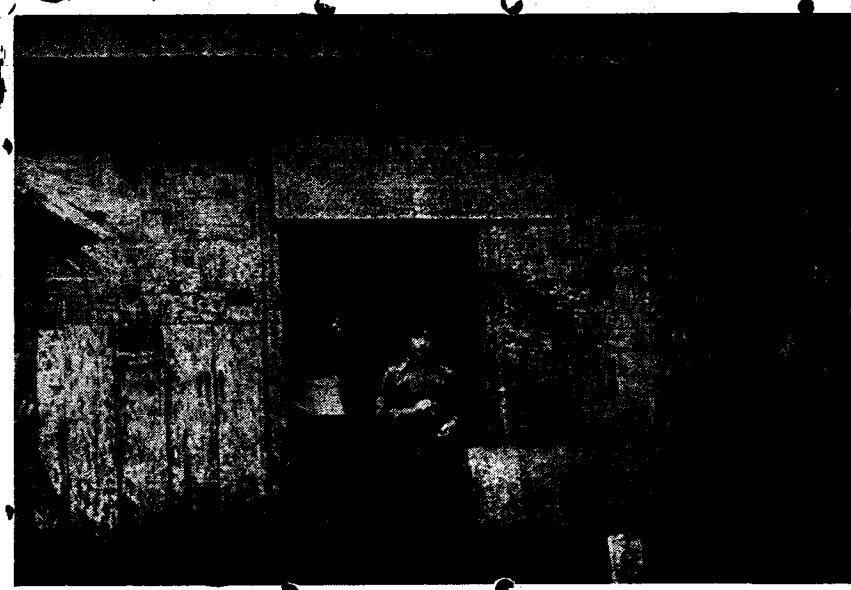
विकलांगों का पुनर्वास

सफल पुनर्वास के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है इस कारण भारत सरकार विकलांगों के लिए एक विशेष छावन्वृति कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान चालू 4507 छावन्वृतियों के अलावा मुविधाओं का विस्तार करने के लिए काफी बल दिया गया है। 1976 में 17 विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा लगभग 1650 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के उपरान्त रोजगार में लगे ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 15,500 हो गई। 1976-77 के दौरान विकलांगों के कल्याण कार्य में लगे 203 स्वयंसेवी संगठनों को 90.82 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई है। 1975-76 में 90 स्वयंसेवी संगठनों को 65 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, ने मिठले वर्ष के दौरान सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इस परिषद् का गठन गत वर्ष डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में अनौपचारिक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस योजना में सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों में वर्तमान सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत करने, नए केन्द्र खोलने तथा अपेक्षाकृत कमज़ोर सहकारी संस्थाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की व्यवस्था है ताकि इन पाठ्यक्रमों में (अधिकाधिक लोग भाग ले सकें)। यह जानकारी नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत परिषद् ने वर्ष 1976-77 में उड़ीसा में बारीपाड़ा में एक नया केन्द्र खोलने तथा मशीबरा (हिमाचल प्रदेश), भरतपुर (राजस्थान) जम्मू (जम्मू तथा कश्मीर), कर्लिपोंग (पश्चिम बंगाल) तथा देवगढ़ (बिहार) स्थित पांच वर्तमान सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत करने के लिए 4:30 लाख रुपए मंजूर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सहकारी समितियों के कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, उनके ढाँचा और संगठन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं और उनके लक्ष्यों में महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं तथा प्रयासों को नई दिशा दी गई है। इस प्रकार सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों के शिक्षण ने और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है।

इस समय एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान तथा बैंकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान है जो सेवारत कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करता है। देश में 10 सहकारी



सहकारी प्रशिक्षण को सुविधाओं में वृद्धि

प्रशिक्षण कालिज श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हैं और 66 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कनिष्ठ स्तर कर्मचारियों के कार्यक्रम राज्य सहकारी संघों द्वारा चलाए जा रहे हैं किन्तु बिहार, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। गोवा का केन्द्र गोवा राज्य सहकारी बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। आनंद प्रदेश तथा तमिलनाडु में ये केन्द्र सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। इनके निर्वाचित प्रबन्ध मण्डल हैं।

इन राज्यों में इन केन्द्रों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण राज्य सहकारी संघों द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इन्हें सम्पूर्ण शैक्षणिक सहायता तथा मार्गदर्शन दिया जाता है।

वर्ष 1976 में त्रिवेन्द्रम में एक नया सहकारी प्रशिक्षण कालिज खोला गया जिससे ऐसे कालिजों की कुल संख्या 16 हो गई है और बारीपाड़ा, उड़ीसा में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया जिससे देश में प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 65 से बढ़कर 66 हो गई।



केन्द्रीय योजनाएं

विभाग वहाँ सी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं चला रहा है। इनमें ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन, महिला मण्डलों का विकास करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना तथा एसोसिएट महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। युवक मण्डलों की कार्यपद्धति के बारे में राष्ट्रीय समुदायिक किकास संस्थान द्वारा अध्ययन शुरू किया गया

है। आशा है यह अध्ययन अगले वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदार के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। लगभग 60 औद्योगिक व्यापारिक घरानों ने कृषि विस्तार और ग्रामीण विकास के कार्यों में पहले ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। औद्योगिक और व्यापारिक घरानों का सहयोग बहुत उत्साहवर्धक रहा है।



एक बार गांधी जी ने कहा था 'जब तक देश में गरीबों का उत्थान नहीं होगा भारत आगे नहीं बढ़ सकता । जब तक स्वराज्य की रोशनी भारत के गांवों में नहीं पहुंचती तब तक हमारी आजादी का कोई महत्व नहीं होगा' ।

आजादी के 30 वर्ष बीत चुकने पर भी गांधी जी की कही हुई बात पर हमारे आयोजक कोई अमल नहीं कर सके, और निरन्तर ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहे । विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत में 47 करोड़ की जनता तो केवल गांवों में बसी हुई है जो कुल जनसंख्या का 80 फीसदी भाग है और जिनमें 90 फीसदी व्यक्ति कृषि व्यवसाय में संलग्न होकर राष्ट्रीय आय के 45 फीसदी भाग के निर्माण में योगदान करते हैं । वस्तुतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो वर्षों से उपेक्षा की शिकार बनी हुई है ।

उनको बहां से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई अन्तर नहीं आएगा । अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है । ऐसे व्यक्तियों की संख्या गांवों में बहुतायत में पाई जाती है । भगवती कमटी (1972) ने ग्रामीण वेरोजगारों की संख्या 161 लाख बताई है । भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री बी० बी० गिरि का कहना है कि यदि वेरोजगारी इसी गति से बढ़ती रही तो 1980 में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने वाली वेरोजगारी 4९ करोड़ पर पहुंच जाएगी जो, मैं समझता हूं, वेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति होगी । यदि इन आंकड़ों पर जरा भी विश्वास किया जाए तो क्या हमारी आर्थिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य इन वेरोजगारों को रोजगार दिलाना नहीं होगा ? यदि होगा तो वे कौन से साधन होंगे जिनसे रोजगार की व्यवस्था की जा सके ? ये प्रश्न हमारे सामने हैं ।

से सम्बन्धित है, निर्माण कार्यक्रमों को चालू किया जाए अर्थात् गांवों में सड़क, पुल, रेल, बांध आदि के कार्यक्रम को चालू करके रोजगार को बढ़ावा देना उचित है ।

हमारी नीति का दूसरा प्रश्न ग्रामीण कृष्ण ग्रस्तता की समस्या से है । भारतीय कृषक एक के बाद एक प्रत्येक वर्ष उधार लेता है किन्तु यह अपना कृष्ण चुका नहीं पाता । इसका कारण या तो कृष्ण की अधिकता होती है अथवा उसकी कृषि उपज की अपर्याप्तता । किसान जिस खेत पर काम करता है छोटी-छोटी विवरी हुई जोतों में बंटा हुआ है । मानसून की कृषा मात्र बना हुआ है । मानसून न आना व अधिक आना दोनों ही स्थितियां उनकी बर्बादी का कारण बनती हैं । इसलिए किसान बांध व कुएं बनाता है व कृषि उपकरण खरीदना चाहता है जिसके लिए उसे भारी मात्रा में ऊचे व्याज पर कृष्ण लेना पड़ता है ।

ग्रामीण विकास : नई व्यूह रचना ★

एच० आर० बिजारनिया

सरकारी फाईलों में इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकती है कि ग्रामीण किन हालातों में गुजर रहा है लेकिन एक ग्रामीण होने के नाते मैं जानता हूं कि गांवों का क्या हाल है । आज आवश्यकता है कि उनके विकास के लिए कदम बढ़ाए जाएं ।

ग्रामीण विकास का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें असीमित कार्य किया जा सकता है । प्रथम सबाल ग्रामीण जनसंख्या की वेरोजगारी को दूर करने का है । राष्ट्र के आर्थिक विकास में वेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका भयावह रूप हमें गांवों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, कृषि व्यवसाय ग्रामीण के जीविकोपार्जन का मुख्य धन्धा है जिसमें लगे हुए बहुत से व्यक्ति वेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं । देखने में ऊपर से बैंक काम में लगे हुए मालूम होते हैं परन्तु यदि

सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है । अतएव क्यों न हम कृषि उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा दें ताकि उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या को कम किया जा सके, बचे हुए अतिरिक्त श्रमिकों को कृषि सहायक उद्योग धन्धों में लगाया जाए जिनमें रोजगार की अधिक सम्भावनाएं हैं । एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आज छोटे उद्योगों में प्रति श्रमिक 1,757 रुपये की अचल पूँजी लगी हुई है और बड़े उद्योग में प्रति श्रमिक यह पूँजी 13,386 रुपये है । रोजगार पूँजी अनुपात के आधार पर इतनी ही पूँजी में छोटे उद्योगों में 7.5 गुना अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है । अतएव आज इन उद्योगों का विकास व विस्तार कर ग्रामीण रोजगार के अवसरों में बढ़ि बननी चाहिए ।

दूसरा कदम जो रोजगार अवसरों

में स्वस्थ विकास के लिए व उचित कृष्ण सुविधा दिलाने हेतु वित्तीय समितियों की स्थापना की गई । सहकारी समितियां व व्यापारिक बैंकों की शाखाएं बड़े शोरगुल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई । रिजर्व बैंक को ग्रामीण कृष्ण व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया । 1955 में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना का किया जाना व 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इस समस्या के सुलझाने के प्रयास किए गए । हाल ही के वर्षों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कर इस दिशा की ओर सराहनीय कदम उठाया गया है । लेकिन समस्या अब भी बही है जो दशाविद्यों पहले थी । अखिल भारतीय ग्रामीण कृष्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट होती है कि किसानों की कृष्ण-आवश्यकता की पूर्ति में व्यापारिक बैंक सबसे ज्यादा

आलोचना का विषय रहीं हैं। इनका भाग निरन्तर घटते हुए 6 फीसदी रह गया है और सहकारी समितियों का भाग केवल 16 फीसदी ही है जबकि निजी समितियों द्वारा 80 फीसदी क्रृष्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। यह हमारे सामने कटु सत्य रहा है कि क्रृष्ण-आवश्यकताओं के लिए किसानों को साहूकारों की शरण में जाना पड़ता है जिस पर उसे ऊंचा ब्याज चुकाना होता है। आज यदि शाखा विस्तार किया जा रहा है तो इससे ग्रामीण कोष का शहरों में जाने का रास्ता और बन गया है।

नई व्यूह रचना में शाखा विस्तार को ही अपने कार्यक्रम का अंग नहीं बना लेना चाहिए यद्यपि शाखा विस्तार अपने आप में जरूरी है जिससे ग्रामीण बैंकों की स्थापना व विस्तार आशाजनक साबित हो सकता है। लेकिन मूलभूत प्रश्न कार्यरत बैंकों की कार्यप्रणाली को सरल बनाने का है।

आज भी एक अशिक्षित ग्रामीण किसान मामूली सी कागजी कार्यवाही को बहुत बड़ा भार समझता है जबकि हमारे बैंकों की कार्यवाही से महीनों तक किसान परेशान होता है जिसको अन्तोगत्वा बिना रिश्वत के पूरा नहीं कर पाता है। उसके लिए सरकारी कर्मचारी देवता तुल्य है जिसको समझाने व मनाने की विधि से वे वाकिफ नहीं हैं। मेरा तो यही सुझाव है कि क्रृष्ण देने के लिए बैंकों द्वारा समय-समय पर शिविर लगाने चाहिए और आवश्यक कर्मचारी उसी स्थान पर मौजूद होने चाहिए।

दूसरी नीति यह है कि पुराने क्रृष्णों के सम्बन्ध में नियम बनाकर उन्हें समाप्त कर दिया जाए तथा नए क्रृष्णों पर नियन्त्रण रखा जाए, जिससे प्रयत्न

यह हो कि अत्यावश्यक और उत्पादक प्रयोजन के लिए ही उधार की सुविधा मिले। साहूकारों की गतिविधियों को रोकने के लिए उनका पंजीकरण करवाना जरूरी कर दें व उनके लिए लाईसेन्स की व्यवस्था लागू कर दें, जिससे ब्याज की अविकल्पना दर भी निश्चित हो। इन सबके जांच पड़ताल के लिए एक जांच व्यूरो की स्थापना करना भी आवश्यक है।

अन्तिम सवाल जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित है, शिक्षा और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण का है। आज देश में 30 फीसदी लोग ही शिक्षित कहलाने के अधिकारी हैं। गांवों में तो यह प्रतिशत और भी कम है। मुश्किल से 8-10 फीसदी व्यक्ति इस श्रेणी में आते होंगे। इसमें स्त्रियों की संख्या नगण्य सी है। इतनी बड़ी संख्या के निरक्षर व्यक्तियों को कैसे कृषि की आधुनिक विधि समझा सकते हैं? उन्नत बीज व रासायनिक खाद के बारे में उनका क्या ज्ञान हो सकता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रचार इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिसमें कृषकों को कृषि तकनीकी शिक्षा के लिए जानकारी दी जाए।

दुर्भाग्य से कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों ने ग्रामीण भोजन, पोषण व स्वास्थ्य की समस्याओं पर समग्र दृष्टि से विचार ही नहीं किया।

पीने के शुद्ध पानी का अभाव है। नदियों, नालों, तालाबों का पानी आज भी उन्हें पीने को मिलता है। उचित व पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के न होने से साधारण सी बीमारी से ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वह पर्याप्त जानकारी के अभाव में बड़ी बीमारी का

रूप बन जाती है। परिवार का सही रूप से लालन-पालन नहीं हो पाता। शिक्षा की कमी से विवेकहीन जनसंख्या वृद्धि में सहयोग देते हैं। महिलाएं, जिनसे परिवार कल्याण संबंधित है, उन्हें परिवार कल्याण के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, ताकि स्वस्थ व सही परिवार को जन्म दे सकें। प्रौढ़ शिक्षा व प्रशिक्षण शिविरों के माध्यमों से ऐसी जानकारी दें ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या के समाधान में सहायक हो सकें।

ग्रामीण विकास

आज ग्रामीण पुनर्निर्माण देश की प्राथमिक आवश्यकता है। अगर हम वास्तव में गरीबी समाप्त करना चाहते हैं तो ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर सुधारने की ओर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। नई सरकार ने गांधी जी के कदमों पर चलने का बचन लिया है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस आवश्यकता को महसूस किया है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के बजाय कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात सोची जा रही है, व रोजगार प्रधान छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना पर अधिक जोर देने की आवाज उठ रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए नई नीति की घोषणा की है। हाल ही में घोषित 10 वर्षीय योजना से नई संभवानाएं बनी हैं जो ग्रामीण विकास के लिए दिशा निर्देश कर सकती हैं।

व्याख्याता
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर



कुरुक्षेत्र : अगस्त 1977

हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति के कीर्तिमान

★ रघुनन्दन प्रसाद शर्मा

जीवन में गति का महत्व सदा ही रहा है। गतिहीन जीव मृतक के समान होता है। वैज्ञानिक युग में प्रगति का मूल आधार भी गति ही है। किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी सम्पन्न करने में ही उसकी सफलता निहित है। जल्दी की इस आवश्यकता ने हर चीज के लघु रूप बनाने की प्रक्रिया को जन्म दिया है। आशुलिपि का अविष्कारभी उसी प्रक्रिया की एक शृंखला है। कोई व्यक्ति कितनी ही जल्दी और कितना ही अधिक क्यों न बोले उसे शीघ्रता से कुछ संकेतों में लिपिबद्ध करने को ही आशुलेखन की संज्ञा दी गई है।

यह ठीक है कि युग में आशुलिपि का प्रचलन बड़ी तेजी से हो रहा है परन्तु इस प्रकार की लेखन-पद्धति की कल्पना भी आज की है, यह कहना उचित न होगा। एक किवदन्ती के आधार पर इस प्रकार की लेखन पद्धति का सम्बन्ध महाभारत के रचनाकाल से भी जोड़ा गया है। कालीदास तथा तमिल की पुरानी रचनाओं में ऐसे लेखकों का उल्लेख मिलता है। हिन्दी में भी आशुलेखन का प्रचलन काफी समय पूर्व हो चुका था परन्तु इसके लिखने की लिपियाँ कौन-कौन सी थीं तथा उनमें कितनी गति से लिखा जाता था, यह जात नहीं है। जहां तक आज के हिन्दी आशुलेखन का प्रश्न है, उसमें कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं और सभी अंग्रेजी की आशुलिपि की प्रणालियों पर आधारित हैं।

किस-किस व्यक्ति ने कितनी-कितनी गति प्राप्त की, इसका कोई प्रामाणिक लेखा-जोखा 1949 से पहले का उपलब्ध नहीं है। सन् 1949 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 28वें अधिवेशन के अवसर

पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सर्वप्रथम अखिल भारतीय हिन्दी संकेत लिपि की प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सर्वश्री बालकृष्ण मिश्र और महावीर प्रसाद सारस्वत ने क्रमशः 170 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलेखन करके प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इन महानुभावों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 'संकेत लिपि रत्न' की उपाधि से सम्मानित किया। किन्तु इसके पश्चात् इस क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। हिन्दी आशुलेखन के क्षेत्र में किसी भी ऐसी प्रतियोगिता के अभाव में इसमें ऊँची गति का न निकल पाना इस कला में रुचि एवं प्रोत्साहन का अभाव ही माना जा सकता है।

इस कला को प्रोत्साहन देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 'केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्' का माना जा सकता है, जिसने हिन्दी में आशुलिपि प्रतियोगिता का नियमित रूप से आयोजन करके अतेक व्यक्तियों को हिन्दी में ऊँची से ऊँची गति पर आशुलेखन के लिए अवसर उपलब्ध कराए। परिषद् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी का प्रचार व प्रसार करने वाली एक स्वयं सेवी संस्था है जिसके सभी पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। परिषद् द्वारा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रचना-पैदा करने की दृष्टि से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उसमें से एक हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता भी है। इत्य प्रतियोगिता में जहां कार्यालयों में ऊँची से ऊँची गति पर आशुलेखन करने वाले

उपलब्ध होने लगे, वहां इस कला में नए-नए कीर्तिमान भी स्थापित होने लगे।

परिषद् की प्रदम आशुलिपि प्रतियोगिता सन् 1962 में दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 100,120,150 और 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगियों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। इस वर्ष प्रथम और द्वितीय स्थान सर्वश्री रविदत्त और श्याम चन्द्र श्रीवास्तव ने प्राप्त किया। प्रतियोगियों द्वारा दिखाई गई रचना और उसके परिणामों से उत्साहित होकर 1963 में 200 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी आशुलेखन का प्रबन्ध किया गया जिसमें श्री शरचन्द्र चतुर्वेदी ने सफलता प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया।

1964 में आशुलिपि प्रतियोगिता दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ, पटना, भोपाल, अयपुर और वार्षदई में भी आयोजित की गई। सभी केन्द्रों पर 100,120 और 150 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की व्यवस्था की गई। 180 और 200 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की व्यवस्था केवल दिल्ली केन्द्र पर ही की गई थी। इस वर्ष भी 200 शब्द प्रति मिनट के गति वर्ग में प्रथम स्थान श्री चतुर्वेदी ने ही प्राप्त किया। 1965 में आयोजित इस प्रतियोगिता में 200 शब्द प्रति मिनट की गति पर सफलतापूर्वक लिखने वालों में सत्य प्रकाश मनोजा का नाम उल्लेखनीय है।

1966 में दिल्ली केन्द्र पर 220 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी आशुलेखन की व्यवस्था की गई। जिसमें सर्वश्री शरचन्द्र चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश

मनोचा ने सफलतापूर्वक आशुलेखन करके क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1967 और 1968 में 100, 120, 150, 180, 200 और 220 शब्द प्रति मिनट पर आशुलेखन की प्रतियोगिताएं रखी गईं 1968 में 220 शब्द प्रति मिनट पर सफलतापूर्वक आशुलेखन करके प्रथम स्थान श्री सत्य प्रकाश मनोचा ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी रहे।

वर्ष 1969 में दिल्ली केन्द्र पर अन्य गति वर्गों के अतिरिक्त 230 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 व्यक्तियों ने डिटर्मिनेंट लिखकर इस शृंखला में एक नया कीर्तिमान जोड़ा। प्रथम और द्वितीय स्थान क्रमशः श्री सत्य प्रकाश मनोचा और श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी ने ही प्राप्त किए। 1970 में 230 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन करने वालों में श्री जगदीश नारायण शर्मा का नाम उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष भी प्रथम स्थान श्री सत्यप्रकाश मनोचा ने ही प्राप्त किया और उन्होंने लगातार 3 वर्ष तक अखिल भारतीय प्रथम स्थान प्राप्त करके 1970 में इस प्रतियोगिता की चल शील्ड स्थायी रूप में ले ली।

परिषद् के द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता निरन्तर लोकप्रिय होती जा रही थी और उच्च गति में आशुलेखन करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। सन् 1971 में 230 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने वालों की सूची में एक और नया नाम श्री गोपाल दत्त विष्ट का जुड़ गया और इस वर्ष इन्होंने ही अखिल भारतीय प्रथम स्थान प्राप्त किया।

1972 में आशुलिपि प्रतियोगिता के उच्चतम गति के वर्गों में सफलतापूर्वक आशुलेखन करके सर्वश्री मनोचा और गोपाल दत्त विष्ट ने क्रमशः प्रथम और

द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1973 और 1974 में भी प्रथम स्थान श्री सत्य प्रकाश मनोचा ने ही प्राप्त किया और लगातार 3 वर्षों तक फिर प्रथम रह कर उन्होंने दूसरी चल शील्ड भी स्थायी रूप से लेकर हिन्दी आशुलिपि की प्रतियोगिता ही नहीं बरत् किसी भी प्रतियोगिता के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। 1974 में श्री गोपाल दत्त ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1976 में श्री विष्ट ने 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर सफलतापूर्वक आशुलेखन करके अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया।

इस प्रकार परिषद् ने नियमित रूप से आशुलिपि प्रतियोगिता का आयोजन करके न केवल ऊंची से ऊंची गति पर आशुलेखन की व्यवस्था करवाई बल्कि अनेक व्यक्तियों को इस दिशा में प्रेरित करने का महान कार्य किया। हर वर्ष नए-नए प्रतिभावान् आशुलिपिकों और रिपोर्टरों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके नए-नए कीर्तिमान स्थापित कराए। प्रोत्साहित हुए व्यक्तियों में सर्वश्री सत्यप्रकाश मनोचा एवं श्री गोपाल दत्त विष्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने हिन्दी आशुलिपि में 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति प्राप्त करना कठिन कार्य नहीं है। इनके अतिरिक्त उच्च गति वर्गों में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में सर्वश्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी, जगदीश नारायण शर्मा, श्यामनाथ टंडन, मनमोहन लाल गुप्त एवं मोहनचन्द्र तिवारी के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये सभी महानुभाव लोक सभा एवं राज्य सभा में संसदीय रिपोर्टरों के रूप में कार्यरत हैं।

श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी का नाम

हिन्दी आशुलिपि के इतिहास में विशेष महत्व का रहेगा क्योंकि उन्होंने उस समय इस क्षेत्र में प्रवेश करके उच्च से उच्च गति आशुलेखन किया, जबकि बहुत कम व्यक्ति ही इस क्षेत्र में आगे आ रहे थे। उनकी तपस्या ने ही आगे आने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा दी। श्री गोपालदत्त विष्ट ने अंग्रेजी आशुलिपिक के रूप में कार्य करते हुए भी हिन्दी आशुलिपि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करके सराहनीय कार्य किया। 1965 की आशुलिपि प्रतियोगिता में 100 एवं 120 शब्द प्रति मिनट की साधारण गति से बढ़कर 1971 में 230 शब्द प्रति मिनट और 1972 में 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन करके उन्होंने अखिल भारतीय प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करके उन लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया जो इस कला में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। श्री विष्ट उपर्युक्त सभी महानुभावों में सबसे कम उम्र के हैं और न्यून्तम समय में उच्चतम गति प्राप्त करने का श्रेय भी उन्हीं को है।

हिन्दी आशुलेखन की कला के विकास के लिए अभी बहुत व्यापक क्षेत्र पड़ा हुआ है। धीरे-धीरे इसमें और भी ऊंची गति की प्रतियोगिताएं आयोजित करके नए-नए कीर्तिमान जुड़वाएं जा सकते हैं। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब अधिक ओष्ठ आशुलिपिक और रिपोर्टर इस ओर आगे बढ़ें। पुरस्कार, पदक प्रशस्ति-पत्र तो प्रोत्साहन मात्र हैं। वास्तव में तो इस समय जो लोग इस क्षेत्र में ऊंचे उठेंगे वे राजभाषा हिन्दी के भावी भवन की नीव के मजबूत पत्थर माने जाएंगे। वे एक नए इतिहास के निर्माता होंगे और हिन्दी भाषा के गौरव होंगे।



हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता की कड़ी है

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी

धर्मेन्द्र पाल सिंह

'मृत व्यापार' सिद्धान्त के प्रवर्तक
एडम सिम्य और उसके अनुयायियों ने श्रमिकों को भी उत्पादन का एक साधन मात्र समझा। इससे उत्पन्न शोषण की प्रवृत्ति के कारण मालिक और मजदूर के सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण रहे। लेकिन दोनों महायुद्धों के दौरान औद्योगिक शान्ति का महत्व-उभर कर समझे आया। इससे दोनों वर्गों के मध्य उत्पन्न शोषणों की आवश्कता तथा संयुक्त विचार-विमर्श की भावना का जन्म हुआ। सबसे पहले विटेन में 1916 में विट्ले रिपोर्ट में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों की राय भी जानने की सिफारिश दी गई। किन्तु सर्वप्रथम संयुक्त राज्य ने दूसरे महायुद्ध के दौरान उद्योगों में 'संयुक्त परिषद्' बनाकर इस विचार को क्रियान्वित किया।

महायुद्ध के बाद स्कैन्डनेविया के देशों में श्रमिकों के प्रबन्ध में भागीदारी के सफल प्रयोग ने अन्य लोकतान्त्रिक देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इस प्रयोग की सफलता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वीडन में औद्योगिक विवादों के परिणामस्वरूप कभी भी साल भर में 20 हजार से ज्यादा श्रम घट्टों का हर्जा नहीं हुआ। कभी-कभी तो यह क्षति घटकर मात्र 5 हजार श्रम घट्टे तक रह जाती है।

1956 के भारतीय औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया है 'समाजवादी लोकतान्त्रिक देशों के विकास के संयुक्त कार्य में श्रमिक भी भागीदार है और उसे उत्साहपूर्वक इस कार्य में भाग लेना चाहिए—उद्योगों में संयुक्त विचार-विमर्श होना चाहिए तथा श्रमिकों को प्रबन्ध में लेना चाहिए।' इसी भावना से प्रेरित हो दूसरी योजना के दौरान एक भारतीय अध्ययन दल को

यूरोप के कुछ देशों के दौरे पर भेजा गया। पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में, श्रमिकों की प्रबन्ध में हिस्सेदारी सम्बन्धी इस अध्ययन मण्डल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। अन्ततः तीसरी योजना में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 'संयुक्त प्रबन्ध परिषद्' की स्थापना की गई। यहां यह बता देना आवश्यक है कि इससे पूर्व 1947 के औद्योगिक विवाद कानून में भी 'वर्क्स कमेटी' बनाने का प्रावधान है। लेकिन 1975 तक यह योजना कागजों पर अधिक रही।

जैसा कि प्रायः समझा जाता है प्रबन्ध किसी वर्ग विशेष का कार्य नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोटे या बड़े किसी भी पद पर हो, हिस्सा लेता है। एक वैल्डर जो अपनी समझ-वूक्स से औजारों तथा संसाधनों के न्यूनतम प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन करता है, अपने तकनीकी कौशल के कारण प्रबन्ध में भागीदार बन जाता है। अतः श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी एक श्रेष्ठ विधि है। इसे अपनाने से उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी के साथ-साथ औद्योगिक वातावरण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।

भारत में 20 करोड़ श्रमिकों की विशाल संस्था का मात्र 10 प्रतिशत ही संगठित है। स्पष्ट है कि प्रबन्ध में भागीदारी की योजना शुरू में इस क्षेत्र में लागू की जाएगी। यूं भी हड्डताल, तालाबन्दी व छटनी पर अंकुश लगाने के इससे अच्छा कोई अन्य उपाय नहीं है। 1973 और 1974 में 3 करोड़ श्रम घट्टों का हर्जा हुआ। लेकिन 1975-76 के दौरान इसमें 50 से 90 प्रतिशत तक की कमी हुई।

श्रमिकों की प्रबन्ध में हिस्सेदारी

की व्यवस्था के अन्तर्गत कारखाने तथा फैक्ट्री के प्रत्येक विभाग या शाप में एक 'शाप कौन्सिल' की स्थापना की जाती है। अधिकतम 12 मदर्सों वाली इस कौन्सिल में गैरेजमैन्ट तथा मजदूरों के आधे-आधे प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव शाप के कर्मचारियों में से ही किया जाता है। यह कौन्सिल दो वर्ष के लिए चुनी जाती है तथा माह में एक बार इसकी बैठक होना जरूरी है। इसका कार्य शाप के उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। इसमें नियंत्रण बोर्ड से न होकर परस्पर सहमति से किए जाते हैं।

प्रत्येक इकाई में एक 'संयुक्त परिषद्' (जार्डिट कौन्सिल) भी होती है। इसमें भी दोनों एक्षों को वरावर प्रतिनिधित्व मिलता है। तीन माह में एक बार इसकी बैठक होना जरूरी है। यह अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग-प्रतिदिन की समस्याओं तथा 'शाप कौन्सिल' सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करती है।

भागीदारी की यह योजना अभी तक केन्द्र के आधीन 472 इकाइयों तथा राज्यों के अन्तर्गत आने वाली एक हजार इकाइयों में लागू की जा चुकी है। कुल मिलाकर 25 लाख मजदूर प्रबन्ध में भागीदार बन चुके हैं।

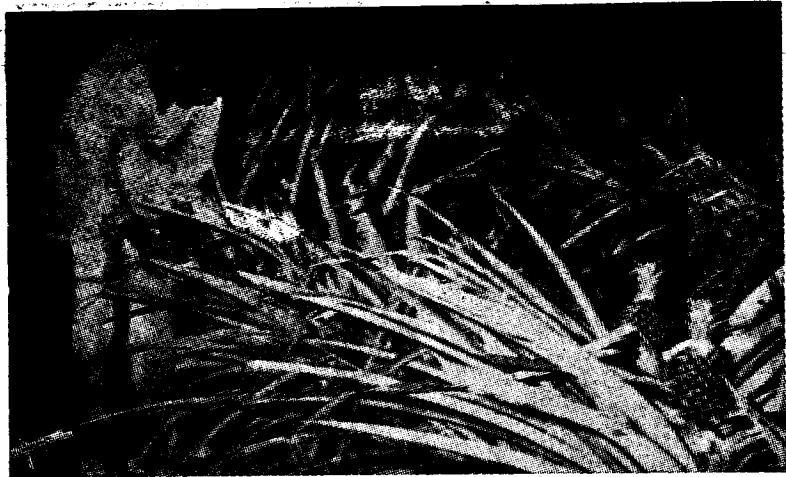
किन्तु निजी क्षेत्र में इस योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं किया गया है। पूँजीपति अभी तक मालिक व नौकर की सँडी-गली परम्परा से चिपके हैं। समय आ गया है कि उन्हें अपने लृदीवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन कर राष्ट्रीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उप-सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान कनाट प्लेस, नई दिल्ली

मणिपुर राज्य भारत के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। जब कि भारत की 1974-75 में प्रति व्यक्ति आय 985 रु० थी तो मणिपुर राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी केवल 684 रु०। यहाँ की अर्थव्यवस्था की धूरी अब भी खेती है। राज्य की 57 प्रतिशत आय खेती से ही मिलती है और 70 प्रतिशत जन संस्था खेती-बाड़ी के धंधों में लगी है, यद्यपि राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी है पर 10 प्रतिशत भूमि बड़ी उपजाऊ है।

झूम खेती

यहाँ की परम्परागत प्रणाली झूम खेती रही है। यानी पेड़ और वनस्पति जला कर उस स्थान को दो-तीन साल के लिए



अनन्नास की खेती

मणिपुर बने महान्, भरे खेत खलिहान ★ श्री एन० भट्टाचार्य

[भारत के सिरमोर हिमालय के पूर्वी अंचल में ऊंची पर्वत मालाओं से घिरे, दुर्गम दुरारोह जंगलों से पटे, किन्तु प्रकृति के यौवन का भरपूर श्रृंगार सजाये आयताकार मणिपुर राज्य ने वस्तुतः छः वर्षों में अनाज की उपज 1.60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1975-76 में 3.03 लाख टन कर दिखाई है और यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति की दुर्दमनीय बाधाओं को चीर कर किस तरह पर्वत का यह संकल्पशील राज्य खेती-बाड़ी में आगे बढ़ रहा है।]

परती छोड़ देना और फिर खेती करना। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह खेती करने का स्थानान्तरण होता रहता है। इस प्रणाली ने पहाड़ी इलाकों में भारी भूमि कटाव की समस्या को जन्म दिया है और जंगलों के कट जाने से जो विषम परिस्थितियाँ अपरिहार्य हैं, उनका सामना इन्हें करना पड़ा है।

अब धीरे-धीरे यह राज्य पुरानी श्रृंखलाओं को तोड़कर नये कीर्तिमान स्थापित करने में लगा है। न केवल खेती-बाड़ी में सुधार हुआ है बल्कि बागवानी में भी काफी तरकी हुई है।

भूमि बटवारा

यहाँ की खेती का दारोमदार यहाँ के छोटे किसानों पर है। खेती की जोतों का बटवारा इस प्रकार है:

कुल जोत	कुल भूमि
प्रतिशत	प्रतिशत

1 हेक्टेयर भूमि तक	40.9	18.9
छोटे किसान (एक से तीन हेक्टेयर)	55.1	68.0
मध्यम और बड़े किसान	4.0	13.1

इससे पता चलता है कि औसत जोत का क्षेत्रफल कितना कम है। छोटी छोटी जोतों में बंदा होने के कारण हम अपेक्षित पैदावार की आशा नहीं रख सकते। फिर भी यहाँ के लोग दिन रात खेतों से अधिकतम उपज लेने के लिए ज़्ज़ रहे हैं।

सिचाई

1970-71 में खेती बाड़ी की जाने वाली कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्र में ही सिचाई होती थी। सिचाई के लिए प्रायः पहाड़ी ढलानों की नदियों से पानी लिया जाता था। 21 करोड़ की लागत वाली लोकटक प्रायोजना द्वारा 24,000 हेक्टेयर भूमि की सिचाई की आशा की जाती है। 23 छोटी सिचाई योजनाओं से लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि के सींचे जाने की आशा है। अधिकांश क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा यानी लगभग 115 से 0 मी० या इससे अधिक होती है।

इसमें सन्देह नहीं कि सिचाई से पर्वतीय अर्थव्यवस्था का काया-कल्प हो सकता है। पश्चिम मणिपुर 13 कबायली गांवों में हमेशा ही खाने की समस्या

मुंह बाये रहती थी। मन्तुर्डु नदी से पानी लेकर दो पम्पसेटों से खेतों में पानी पहुंचाया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल साल भर में ही जिन गांवों में अनाज के लिए हाय-हाय मच्ची रहती थी, वे गांव आत्म-निर्भर हो चले। (कामर्स एनुअल 1975)

दरअसल पानी के बटवारे की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहीं तो पानी ज्यादा है। और कहीं बहुत कम। कहीं पानी से फसल बिगड़ती है और कहीं पानी की कमी से सूख जाती है। यदि पानी ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो अनाज की भरपूर उपज मिल सकती है। इस्फाल में 1971 में भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए प्रयत्न किए गए। पांच जगहों पर बोरिंग की गई और उनमें से दो जगहों से 106 मीटर की गहराई पर और तीन जगहों से 150 मी० की गहराई पर पानी निकल आया। लेकिन पानी की मात्रा काफी नहीं थी।

नयी तकनीक

इस समय केन्द्रीय घाटी की खेती-

बाड़ी वाली भूमि के लगभग 30 प्रतिशत भाग में खेती की नयी तकनीकें अपनायी जाने लगी हैं। अब अधिक उपज देने वाली किस्मों के सुधरे बीजों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। 1974-75 में इन नये चमत्कारी बीजों का इस्तेमाल लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि पर हुआ जबकि 1975-76 में इसके अन्तर्गत 35,000 हेक्टेयर भूमि लायी गयी। नयी तकनीकों में जहां सिंचाई और बीजों का महत्वपूर्ण स्थान है वहां उर्वरकों का भी उतना ही महत्व है। इसलिए उर्वरकों के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया है। नीचे के आंकड़े प्रगति की कहानी बता रहे हैं :—

फी हेक्टेयर किलोग्राम रासायनिक खाद

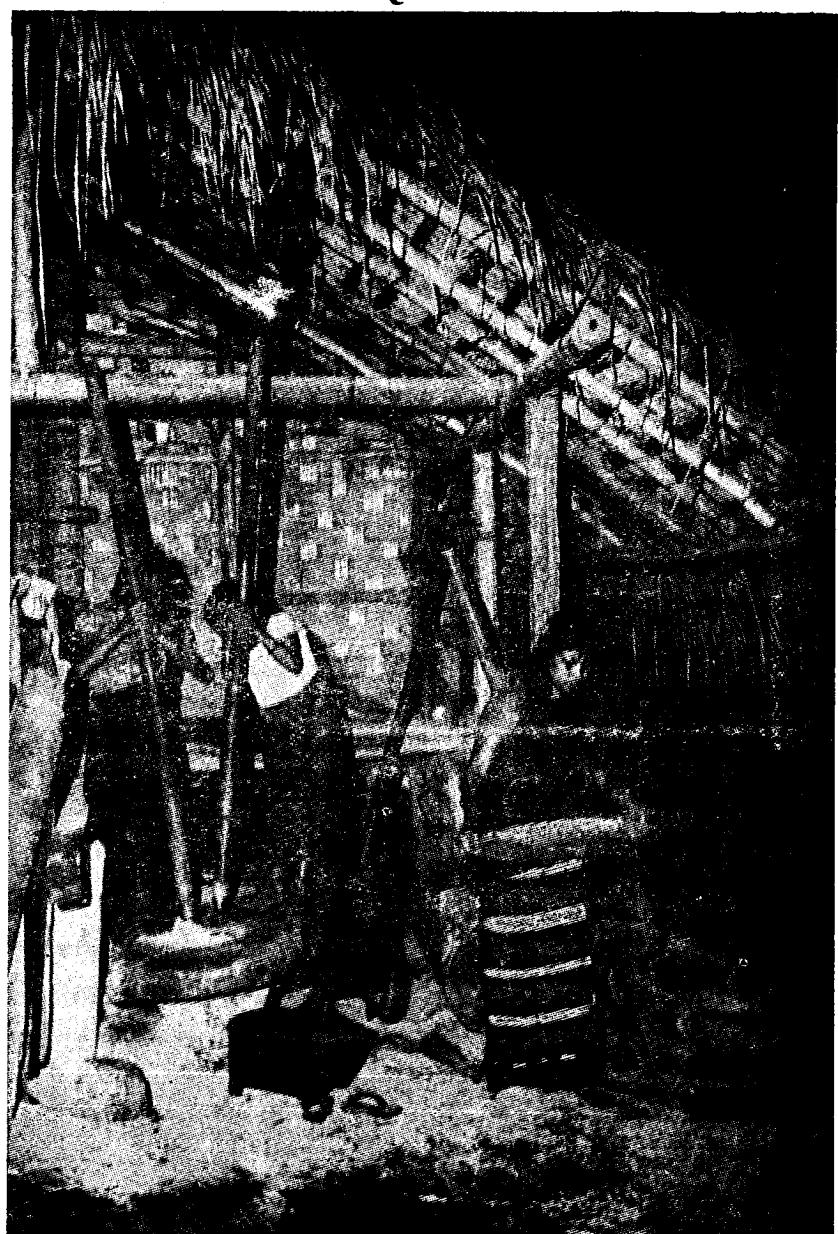
	मणिपुर	भारत
1964-65	1.04	4.05
1971-72	9.44	14.53
1974-75	10.90	15.80

इससे यह भी पता चलता है कि भारत की औसत खपत की तुलना में मणिपुर काफी पीछे है।

इसके अलावा, अब ट्रैक्टरों, पावर-टिलर और दूसरे छोटे औजारों का भी इस्तेमाल होने लगा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मैदानी उपजाऊ इलाकों में तो नये औजार का इस्तेमाल होने लगा है परं पहाड़ी इलाके अब भी पिछड़े हुए हैं। कहीं कहीं अब तक झूम खेती होती है। दरअसल झूम खेती में साल-दो-साल तो भरपूर उपज मिलती है और कबायली लोग इस भरपूर फसल से खुश हो जाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इसके द्वारामी प्रभाव खराब होते हैं। उस जगह भू क्षरण होना शुरू होता है और धीरे-धीर वह इलाका जंजर भूमि में बदल जाता है।

जंगल

यहां की लगभग 27 प्रतिशत भूमि जंगलों से पटी पड़ी है। लगभग 63.6 प्रतिशत भूमि खेती योग्य नहीं है। जंगलों में बड़ी वेशकीमती लकड़ी पैदा होती है। टीक, साल, चीड़, देवदार, फर, सेमल, माचिस के लिए लकड़ी व प्लाइड, बांस



चावल निकालने के लिए धान की कुटाई

बहुतायत से मिलते हैं। ये लकड़ियां उद्योग व व्यवसाय की दृष्टि से कीमती और उपयोगी हैं। केवल जेरी और बारक नदी वाले क्षेत्रों में ही सलाना

3 लाख मिट्रिक टन बांस पैदा होते हैं।

झूम खेती यहां बरसों से चली आ रही है। जैसा कि उपर बताया जा चुका है कि झूम खेती से इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। जंगलों के कटने से न केवल जलवायु और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ता है बल्कि भूमि के कटाव के कारण लम्बे-चौड़े इलाके वीरान हुए जा रहे हैं। कटाव से उपजाऊ जमीन चौपट हुई जा रही है।

इस प्रकार धीरे धीरे ये नंगे पहाड़ और जंगल मणिपुर की खुशहाली को लील रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग ईधन के लिए जंगलों को बराबर काट रहे हैं। इनके कटने से और झूम खेती से जंगलों की शामत आ गई है। इस समस्या पर



नगदा में छोटी सिचाई योजनाएं—इनसे 100 एकड़ धान क्षेत्र की सिचाई होती है

तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इन छलाकों में न तो भूमि संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और न कोई वन-वृद्धि के उपाय अपनाये जा रहे हैं। न तो जल्दी उगने वाले पेड़ों की तरफ ही ध्यान दिया गया है और न कृषि वानिकी की नयी विद्या पर ही जोर दिया जा रहा है।

पशुपालन

हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार छोटे और बहुत बड़े किसानों को पशु-पालन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुर्गी पालन, घेर-बकरी पालन, सूअर-पालन और गाय-भैंस पालन पर अब वहां जोर दिया जा रहा है और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है।

मछली पालन

मणिपुर की राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत भाग मछलियों की विक्री से मिलता है। यहां मछली पालन के लिए भारी गुंजाइश है। प्रतिवर्ष यहां से लगभग 1,000 टन मछली मिलती है।

जनसंख्या

मणिपुर की जनसंख्या 1961-71 के दशक में लगभग 37.53 बड़ी जबकि पूरे देश में इसी दशक में वृद्धि की दर 24.8 प्रतिशत थी, जबकि पूरे देश में खेती बाड़ी का योगदान राष्ट्रीय आय में उतना अच्छा नहीं है, मणिपुर में खेती बाड़ी का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। नीचे के आंकड़ों पर एक नजर डालिए :—

खेती से प्राप्त आय प्रतिशत

	मणिपुर	भारत
1960-61	48.7	52.5
1965-66	49.8	44.2
1970-71	51.1	45.8

अनाज की उपज

मणिपुर में बराबर उपज बढ़ रही है। जहां यह सन् 1960-61 में 1.29 लाख टन थी वहां 70-71 में 1.60 लाख और 75-76 में 3.03 लाख टन हो गयी।

उपसंहार

मणिपुर की खेती के क्षेत्र की यह उन्नति आशाजनक है। परन्तु दो बातों

पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहले बताया जा चुका है कि भूमिकटाव और जंगलों का कटाव विकट समस्या पैदा कर रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देना है। गांवों में केवल 12% गांवों में बिजली है जबकि भारत के 27 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गयी है। बिना बिजली के पम्प नहीं चलाए जा सकते। इस तरह सिचाई में बाधा पहुंचती है। यहां बैंकों की भी लोक-प्रियता नहीं है। न लोगों में पैसा जमा करने की जागरूकता है और न उनके पास साधन ही अधिक हैं। लोग बैंकों की ऋण आदि देने की सुविधाओं के बारे में भी कम ही जानते हैं।

यद्यपि सरकार की योजनाओं पर बराबर काम हो रहा है पर अब भी ये क्षेत्र उपेक्षित हैं। इन लोगों की कर्मठता और निष्ठा तो अनुकरणीय है और निस्सदैह इन गुणों के बलबूते पर मणिपुर की धरती सोना उगल सकती है और प्रकृति की विपुल सम्पदा रूप बदल कर लोगों के घरों में सुख समृद्धि ला सकती है।

(अनु० ब्रजसाल उनियाल)

धूप, वायु और बिजली

डडले फर्नाडो ★

श्रीलंका के ठीक दक्षिण में एक छोटे से गांव के लिए बिजली पैदा करने की दृष्टि से धूप, वायु और कृषि—पशुओं (उनका खाद) को एक साथ उपयोग में लाया जा रहा है।

विश्व में यह पहला अवसर होगा जबकि खाद में खमीर उठाकर धूप, वायु और जीव गैस से प्राप्त ऊर्जा की बैटरी में जमा किया जाएगा ताकि उससे समाज की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

इस वर्ष के अन्त तक पत्तियोपाला के गांव में एक ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र चालू होने की आशा है। यहां प्राप्त सफलताएं तीसरे विश्व के लिए प्रकाश, पीने के पानी, सिचाइ के लिए पानी निकालने और फार्म के उपकरण चलाने के लिए बिजली के नये-नये साधनों के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण घटनाएं होगी। यह केन्द्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और श्री लंका सरकार का संयुक्त प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अफ्रीका और लातिन अमरीका में भी इसी प्रकार के दो अन्य केन्द्र खोले जाने की आशा है।

ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र के भविष्य के बारे में बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डा० मुस्तफा के० तोलबा ने मुझे हाल ही में बताया :

“हम यह जानते ही हैं कि धूप, वायु और जीव गैस को अलग-अलग और एक बड़ी सीमा तक प्रभावशाली रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम ऊर्जा के इन साधनों को एक साथ मिलाकर उपयोग में लाना चाहते हैं ताकि इनमें से कोई भी ऊर्जा, चाहे थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा पैदा करने, विशेषकर

अत्यावश्यक स्तर से भी नीचे का जीवन व्यतीत किये जाने वाले ध्वनियों के विकास के लिए दूसरी अन्य ऊर्जाओं को अपना योगदान दे सके।”

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार डा० आई० एच० उस्मानी के अनुसार ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र एक “तीसरा विकल्प” भी प्रस्तुत करता है। पहला विकल्प सीमित मात्रा में उपलब्ध जलशक्ति से प्राप्त परम्परागत ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन जैसा तेल है जो बहुत ही महंगा हो गया है। दूसरा विकल्प परमाणु ऊर्जा है, यह भी बहुत खर्चीला है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए। इससे प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। डा० उस्मानी कहते हैं कि तीसरे विकल्प से प्रदूषण के किसी खतरे के बिना सस्ते तत्वों से काफी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

पत्तियोपाला में उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न उपकरणों को अलग-अलग तो कई बार काम में लाया जा चुका है लेकिन इससे पहले इन्हें कभी भी एक साथ काम में नहीं लाया गया था। इन उपकरणों का चुनाव ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के अमरीकी वैज्ञानिकों के एक दल ने किया है। ये वैज्ञानिक 1961 से वायु और सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों ने ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र की सम्भाव्यता का अध्ययन किया था।

पत्तियोपाला में जेनरेटर का कार्य करने वाली पवन चक्रियां, “रैकाइन साइकिल इंजन” के साथ लगे सौर ऊर्जा संग्रहक (जिन इन्टरनल कम्बस्टन इंजिन की तरह कम्प्रेशन फेज नहीं होता) और जीव गैस जेनरेटर सब मिलकर आम भंडारण बैटरियों में बिजली भेजेंगे। इन बैटरियों में यह बिजली गांव में भेजी जाएगी।

इस प्रकार के परीक्षण के लिए पत्तियोपाला जैसे स्थान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस स्थान पर भी श्रीलंका के किसी अन्य स्थान की

अपेक्षा अधिक धूप आती है और यहां वर्ष के दस महीनों में आधे से ज्यादा दिन 16 किलोमीटर (10 मील) प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना रहती है। पत्तियोपाला में वर्ष में 11 महीने धूप की तेजी और वायु एक-दूसरे की पूरक रहती है। गांव के पश्चिमों से जीव गैस यूनिट के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाया करेगा।

वंबई के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई 85 घन मीटर (3000 घन फुट) क्षमता की इकाई को दधिण भारत में सफलतापूर्वक चलाकर देखा गया है। इसे अगले महीने (मार्च) में चालू किया जाना था। इससे उर्वरक और बिजली पैदा किए जाने की आशा है।

आधुनिक वायुगति की डिजाइन वाली विभिन्न प्रकार की पवन चक्रियां मंगाने के लिए कनाडा, स्विस, अमरीकी और आस्ट्रेलियाई कम्पनियों को आडर दिए गए हैं। अगस्त महीने तक इन पवन चक्रियों के 9 से 16 मीटर (30 से 60 फुट) ऊंचाई पर लगाये जाने की आशा है।

इस प्रणाली का विकास इस ढंग से किया गया है कि तीनों साधनों में से प्रत्येक से बराबर मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। 140 वर्गमीटर (1500 वर्ग फुट) ध्वनि को घेरने वाले संग्रहक, पवन चक्रियां और जीव गैस जेनरेटर में कुल 60,000 के डब्ल्यू एच या 20,000 के डब्ल्यू एच० बिजली, जो कि हर घर में चार बिजलियां जलाने के लिए काफी होगी, और 200 परिवारों के हर व्यक्ति को प्रतिदिन पम्प से निकाला हुआ 38 लीटर (10 गैलन) पानी दिया जा सकता है। बाकी ऊर्जा का उपयोग धान के खेती की सिचाई के लिए किया जा सकता है।



कुछ अनोखी मछलियां ★ अरुण कुमार सिंह

दृष्टि-विद्युत उत्पन्न करने वाली अनोखी मछलियां

हमारी पृथ्वी के तीन चौथाई भाग में पानी ही पानी है और है केवल एक चौथाई भाग में धरती। पानी के इस विस्तृत भंडार में अनेक प्रकार के सरल-तम जीवों से लेकर विशाल और भयावह जटिलतम जीवों की जातियां पाई जाती हैं। इन जीवों का रहन-सहन, खान-पान, शरीर की बनावट और रचना जल में पाई जाने वाली विभिन्नताओं और विशेषताओं, समुद्र की गहराई, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, पानी का ताप तथा वातावरण की अनुकूलता पर निर्भर करता है। सामान्य मछलियों के अतिरिक्त समुद्र की विभिन्न गहराइयों और भौगोलिक परिस्थितियों में अनेक अनोखी मछलियां मिलती हैं जैसे उड़ाकू मछलियां, स्किवड, प्रकाश एवं विद्युत उत्पन्न करने वाली, धोड़ा, फीता, हांगर मछलियां आदि।

1. उड़ाकू मछलियां : इन मछलियों की लगभग 50-55 जातियां हैं। ये 1 फुट या कुछ ज्यादा लम्बी होती हैं। ये पक्षियों की तरह हवा में न तो बहुत देर तक उड़ती हैं और न बहुत दूर तक। इनके सुफानों की बनावट चिड़ियों के पंख की बनावट से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। पर जैसे चिड़िया उड़ते समय अपने पंखों को हिला-हिलाकर अपने शरीर के बोझ को सन्तुलित करती हैं वैसे ये मछलियां सुफानों को हिला-हिलाकर अपने शरीर के बोझ को नहीं साधतीं। ये अपनी चौड़ी पूँछ की सहायता से पानी को दबाकर अपने शरीर को खूब जोर से झटका देती हैं। ऐसा करने से ये पानी की सतह से लगभग 3-4 फुट ऊपर तक उछल जाती हैं। फिर अपने बड़े-बड़े सुफानों को फैलाकर हवा में सौ ढ़े दौड़ा सी मीटर तक उड़ती रहती हैं। इन मछलियों का शरीर चपटा, मुँह का निचला भाग ऊपर के भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा तथा लम्बा होता है। ये मछलियां हमेशा कुछ बनाकर रहती हैं और कुछ बनाकर

एक के बाद एक-एक करके झुंड में ही उड़ती भी हैं। ये छोटी-छोटी मछलियां धोंधें, सीप, केकड़े आदि को खाकर अपना पेट भरती हैं। अतः ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होती हैं।

2. स्किवड मछलियां : हवाई जहाज, जेट, राकेट आदि अपनी विशेष बनावट के कारण तेजी से हवा को चीरते हुए भरटे से उड़ते हैं। ठीक वैसे ही समुद्र की कुछ मछलियां भी पानी को तीव्रता से चीरती हुई निरन्तर आगे बढ़ती रहती हैं और विभिन्न उपायों द्वारा अपने शव्वों एवं आक्रमणकारियों से दूरपनी आत्मरक्षा करती हैं। इन्हें स्किवड कहा जाता है। अभी तक इनकी 32 जातियों के बारे में जानकारी हो पाई है जिनमें से जेट स्किवड, धूआं छोड़ने वाली स्किवड और आंखों को अंधा बनाने वाली स्किवड प्रमुख हैं। समुद्र के अपृष्ठवंशी अर्थात् बिना रीड़ की हड्डी वाले जलजीवों में स्किवड ही सबसे बड़ी होती हैं। 8 इंच से लेकर 50 फुट तक की लम्बी स्किवड समुद्रों में मिलती हैं। सभी जातियों के मुख के चारों ओर दस लम्बे लम्बे हाथ होते हैं। ये पुष्ट और मांसल होते हैं। इनमें से दो हाथ तो काफी बड़े होते हैं, शेष आठ छोटे होते हैं। लम्बे हाथों की सहायता से स्किवड फुर्ती से अपना भोजन पकड़ कर अपने मुख के हवाले करती है। दो बड़ी-बड़ी गोल-गोल ऊंचरी हुई पलक-हीन आंखें बड़ी तत्परता से भोजन की खोज करती हैं। ये मांसाहारी हैं। छोटी-छोटी मछलियों को खाया करती हैं और ह्वेल इनको खाकर अपने पेट की भूख मिटाती है।

3. जेट स्किवड : इन स्किवडों के शरीर की बनावट ठीक जेट विमानों की तरह होती है और जैसे जेट विमान बड़ी तेजी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है वैसे ही ये भी पानी को चीरकर तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। इसीलिए



तो इन्हें स्किवड कहा जाता है। इन स्किवडों के शरीर के भीतर सैकड़ों की संख्या में छोटे-छोटे प्याले होते हैं जो एक बड़े शक्तिशाली पंच की भाँति व्यवस्थित और सुव्यवस्थित कार्य करते हैं। जब स्किवड को आगे जाना होता है तो वह सामने के पानी को खींचकर अपने शरीर के प्यालों में भर लेती हैं फिर बड़ी शक्ति से पिचकारी के रूप में पीछे की ओर छोड़ती हैं। जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है और स्किवड आगे बढ़ती है। जब स्किवड को पीछे की ओर लौटना होता है तो वह प्यालों के पानी बड़ी तेजी से उगलती है, परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है और स्किवड तेजी से पीछे की ओर हट जाती है।

(ब) धूआं उड़ाने वाली स्किवड : कुछ ऐसे स्किवड हैं जो शव्वुओं तथा आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए अपने शरीर के पिछले भाग से काले-काले तरल-पदार्थ के बादल उड़ा देते हैं। इन काले बादलों को देखकर शव्वु घबरा जाता है और स्किवड बचकर भाग

निकलता है। कुछ स्किवड अपने बैरी को धोखा देने के लिए काली स्याही का धुआं छोड़ते हैं जिसके अंधकार में दुश्मन राह भटक जाते हैं और स्किवड को बचकर भाग निकलने का अवसर मिल जाता है।

समुद्र की लगभग 600 मील की गहराई में एक प्रकार के स्किवड पाए जाते हैं जिनका नाम है हैड्रोट्रॉफिस। ये अपने दुश्मन के आगे खूब तेज चमकने वाले पदार्थ की पिचकारी छोड़ते हैं। इस चमचमाते पदार्थ की चकाचोंध से आक्रमणकारी की आंखें चुधिया जाती हैं। विवश होकर उसे अपनी आंखें बन्द करनी पड़ती हैं और स्किवड उसे छोड़कर नौ दो ग्यारह होता है।

3. विद्युत् मछलियाँ : समुद्र की लगभग 111 कि० मी० की गहराई में लगभग 50 प्रकार की ऐसी मछलियाँ होती हैं जो अपने शरीर से विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। इन मछलियों की पूँछ पर एक प्रकार की विद्युत शक्ति पाई जाती है तो मुंह पर दूसरी तरह की अर्थात् इनके पूँछ और मुंह पर विपरीत विद्युत् शक्ति पाई जाती है। इसकी सहायता से ये अपने शरीर से विद्युत उत्पन्न कर सकती हैं। जब इन्हें अपना आहार ढूँढ़ना होता है या शत्रुओं से अपना बचाव करना होता है तब ये अपने शरीर को इस प्रकार मोड़ती हैं कि शरीर के दोनों हिस्से मुंह और पूँछ एक दूसरे के एकदम निकट आ जाएं। दोनों हिस्सों में विपरीत विद्युत होने के कारण इनके शरीर के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बन जाता है जिसमें से चिनगारियाँ निकलने लगती हैं। इन चिनगारियों के प्रकाश में ये अपना आहार और शिकार बड़ी आसानी से ढूँढ़ लेती हैं। इस विद्युत में यदि कोई जल जीव जाने-अनजाने आ गया तो फिर क्या कहने। इतने जोर से झटका खाता है कि विचारा या तो वेहेश हो जाता या फिर बहुत दूर जा पड़ता है। इन मछलियों में टाइपीडों, ईल, कैटफिश और स्टार गेजर मुख्य हैं।

कैटफिश लगभग तीन फुट लम्बी

होती है। इसके शरीर के विद्युत् क्षेत्र में एक स्वस्थ शक्तिशाली घोड़े तक को झटका देकर 8-10 मीटर दूर फेंक देने की क्षमता होती है। इसमें लगातार कई बार झटका देने के बाद कुछ देर के लिए विद्युत् उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तब यह किसी सुरक्षित स्थान में जाकर विश्राम करती है, भोजन करती है, शक्ति संचय करती है ताकि खोई हुई शक्ति को पुनः पा सके। घन्टे-दो घन्टे बाद पुनः झटका देने के लिए तैयार हो जाती है। स्टार गेजर लगभग एक फुट लम्बी होती है। यह पानी में नहीं—बाहर अपनी विशेषता प्रदर्शित करती है। यह प्राय अपने मुंह और अपनी दुम को मोड़कर पास लाकर बालू में इस प्रकार पड़ी रहती है कि सारा शरीर तो बालू की ढेर में छिपा रहता है केवल थोड़ा सा मुंह बाहर रहता है। बेचारे छोटे-छोटे जीव इसके शरीर को छूते ही झटका खाकर अपने होश हवास खो देंते हैं। दक्षिण अमेरिका में इन नाम की एक मछली पाई जाती है जो 500 बोल्ट की विद्युत् उत्पन्न करती है। टाइपीडों के बारे में तो कहा जाता है कि मां जितनी शक्ति की विद्युत रखती है वह तो दूर, जब बच्चे मां के पेट में रहते हैं तभी से झटका देने लगते हैं।

4. प्रकाशोत्पादक मछलियाँ : समुद्र की गहराई जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे प्रकाश और ताप दोनों ही कम होते जाते हैं और दबाव बढ़ता जाता है। सवा डेढ़ कि० मी० की गहराई के बाद तो समुद्र बिल्कुल अंधकार मय तथा बर्फ के समान ठंडा होता जाता और प्रति वर्ग सेन्टीमीटर पर लगभग 2 किवटल दबाव पड़ता है। यही कारण है कि समुद्र को सवा डेढ़ कि० मी० की गहराई के बाद बहुत कम जल जीव पाए जाते हैं, जिनके शरीर प्रायः अंधेरे में चमकते हैं और जिसकी रोशनी में ये जल जीव सरलता से सभी वस्त्रुओं को देख लेते हैं। चूंकि अधिक गहराई में प्रकाश और ताप के अभाव में पेड़ पौधे तथा सामान्य जल जन्तु नहीं पाए जाते, इस लिए अपने भोजन की खोज में कुछ

ऊपर आना पड़ता है तथा वापिस लौटना पड़ता है। इन मछलियों का शरीर प्राय छोटा और गोल होता है। मुंह दांत और जबड़े की बनावट बड़ी विचित्र होती है। वाइपर मछली का मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने बराबर तक के जीवों को बड़े आराम से निगल जाती है। दांत जबड़े इस तरकीब से लगे होते हैं कि शिकार एक बार में मुंह गया तो बस निकल नहीं सकता। स्वालोवर तो अपने से तीन गुने डील डोल वाले शिकार को खड़ा का खड़ा निगल जाती है।

5. घोड़ा मछली : बंगाल की खाड़ी में घोड़े जैसी शक्ल सूरत वाली एक मछली पाई जाती है। इसीलिए इसका नाम घोड़ा मछली रखा गया है। यह अपनी दुम की सहायता से किसी आधार को पकड़कर खड़ी होती है। इसका धड़ दोनों ओर से चपटा तथा पेट उभरा हुआ होता है। सिर कांटों से भरा रहता है। शरीर छल्लेदार हिंडियों का बना केवल एक ढाँचे की तरह दिखाई पड़ता है। धूथन लंबी नली की तरह आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है जिसके द्वारा यह छोटे-छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाती हैं। अनोखी बात तो यह है कि यह मछली अंडों को सेती है। नर के दुम के पास सामने एक धैली होती है। उसी में अंडों को रखे यह उस समय तक धूमती रहती है जब तक अंडे फूट नहीं जाते।

6. ह्वेल मछली : ये दुनिया की सबसे विशालकाय और भयावह जीव हैं। इनकी लम्बाई 125 से 130 फुट और वजन 1600 किवटल होता है। जब ये सांस लेती हैं तो एक फव्वारा सा छूटता है। ये प्रति दो घन्टे के अन्तर से पानी की सतह पर आकर सांस लेती हैं। अगर दो घन्टे से अधिक समय हो जाता है तो डूबकर मर जाती है। यह मछली अंडे नहीं देती बल्कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती है जिन्हें वह स्तनधारी जीवों की तरह धूध विलाकर बड़ा करती है।

7. तेगा मछली : इस मछली का जबड़ा तलवार की तरह का होता है।

मुह भीतर की ओर काफी लम्बा कटा होता है, इसके दांत नहीं होते। यह साधारणतया 5-6 फुट लम्बी होती है। पर कभी-कभी 15-20 की भी मिलती है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा स्लेटी और निचला हूँके लाल रंग का होता है। खाल उभरी हुई होती है और दुम के पास दोनों ओर से जगहों पर थोड़ा सा उभार होता है। तैरते समय यह नाव की पाल के समान प्रतीत होती है।

8. फीता मछली : इसका आकार फीते जैसा होता है। पानी में तैरते समय यह सांप जैसी लगती है। शरीर का पूरा रंग रुपहला होता है और सुफने होते हैं गुलाबी जिसके कारण यह बड़ी सुन्दर दिखाई पड़ती है। ये मछलियां समुद्र की काफी गहराई में रहती हैं। पीठ पर नरम-नरम कांटे होते हैं। मुह छोटा होता है। हमारे देश की फीता मछलियां 7-8 मीटर लम्बी, बेलनाकर शरीर वाली होती हैं। परन्तु इन्हें में पाई जाने वाली फीता मछलियां 20 से 35 फुट लम्बी होती हैं जिनका शरीर चपटा और 1 या 111 फुट चौड़ा होता है।

9. सील मछलियां : ये मछलियां क्या हैं? इन्हें अगर समुद्री शेर कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। ये प्रायः ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। एक नर सील सैकड़ों

मादा सीलों पर अपना अधिकार रखना चाहती है। मादा सील के लिए नर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी-कभी तो युद्ध होता रहता है और ये अपने शिकार को भी नहीं जाते जो मादा सील सबसे अधिक बच्चे उत्पन्न करती है उसके लिए सबसे ज्यादा धमासान युद्ध करना पड़ता है।

10. हांगर या शार्क : इस जाति की मछलियां की अनेक उपजातियां हैं। ये 2-2 फुट से लेकर 50-60 फुट लम्बी तथा 4-6 किलोग्राम से लेकर 50-60 किलोटल वजन वाली होती हैं। ये कई रंग की होती हैं। नीली शार्क, लाल, काली और सफेद शार्क। रंग इनका चाहे जैसा भी हो परन्तु सभी में शरीर के नीचे वाली चमड़ी पर विभिन्न प्रकार की चित्तियां अवश्य ही पाई जाती हैं और इन्हें के कारण ये अन्य जन्तुओं से अलग पहचानी जाती हैं और इनके शत्रु आसानी से इनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। इनकी हड्डियां बड़ी मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं। मुंह के ऊपर तथा आसपास की चमड़ी दानेदार होती है, जो लकड़ी की वस्तुओं पर चमक लाने के साधन के रूप में काम में लाई जाती हैं। इसका मुख छिद्र सामने नहीं होता। इसलिए इसे शिकार पकड़ते

ही तुरस्त उल्ट जाना पड़ता है। तभी यह शिकार को निगल सकती है। इसके मुख्य भोजन में छोटी-छोटी मछलियां तथा जल जीव। कभी-कभी बड़ी शार्क छोटी शार्क को भी खा जाती है। कुछ नरभक्षी शार्क मछलियों के बारे में जानकारी मिली है। सफेद शार्क तो स्नान के लिए आए मानवों के लिए आंख लगाए बैठी रहती है। जैसे ही मानव पानी में प्रवेश करता है ये मछलियां उसे पकड़कर अपने गले के नीचे उतार लेती हैं। इनकी लम्बाई 45-55 फुट तक होती है। ह्वेल की तरह संसार की सबसे विशालकाय हांगर है। वैसे तो यह देखने में भयानक पर बेचारी मानव पर कभी भी आक्रमण नहीं करती है। वाद्यमुखी हांगर अपनी ही जाति की हांगर को निगलकर अपने पेट की ज्वाला शांत करती है। और अन्य नरभक्षी शार्क अपने अंडों को अपनी उदरगुहा में उस समय तक रखती है जब तक कि अंडों से बच्चे निकलकर बड़े नहीं हो जाते।

इसी प्रकार की अनेक अनोखी मछलियां और भी समुद्र की गोद में खेल रही हैं और मानव के कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। कुछ के बारे में जानकारी हो पाई और कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का रास्ता खुला है। ★



कांगड़ा के लोकगीतों में सैनिक पत्नी की विरह वेदना ★ मनोहर लाल

कवि सामाजिक प्राणी है। वह अपने चर्तुर्दिक् समाज से वस्तु तत्वों का संग्रह करता रहता है। देश प्रेम का भाव मनुष्य की व्याप्ति का विस्तार है। प्रत्येक प्राणी को अपनी जन्म भूमि से प्रेम होता है। प्रत्येक प्राणी उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहता है।

सफल राष्ट्रीय भावना वही है जिसमें कवि-कर्म आस्थावान होकर, समसामयिक युग-बोध के सिर पर चढ़ कर बोलता है। जब भी कभी राष्ट्र-सम्पत्ति पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे, तब कवि समाज को ऐसा भाव दे जिसमें स्वाभिमान की अनुभूति हो। जो कवि इस कर्म का निर्वाह कर सकता है, वही सच्चा राष्ट्रकर्मी कहलाएगा। इस संदर्भ में मुझे दिनकर की अधोलिखित पंक्तियां उद्धृत करनी अच्छी लग रही हैं:—

छोनता हो स्वत्व कोई, और तू
त्याग तप से काम ले, यह पाप है।
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो।”

(कुरुक्षेत्र)

कांगड़ा डोगरों की भूमि है। डोगरे जवान देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। आज भी आंकड़ों से यह प्रतिपादित हो जाएगा कि कांगड़ा के सैकड़ों सूरमा कौज में भरती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भारतीय थन-सेना में एक सुविध्यात 'डोगरा-रेजिमेंट' भी है।

1. कांगड़ा के लोक-जीवन में प्रचलित लोकगीतों में सैनिकों के व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। रागात्मक अर्थात् सुख-दुखात्मक जीवन की केन्द्रीय विचार-धारा प्रेम है। कांगड़ा के अधिकांश लोकगीतों में प्रेम की मामिक व्यंजना के साथ-साथ प्रणय तथा राष्ट्रीयता का अद्भुत समन्वय है। प्रायः कहा जाता है, युग की मांग के अनुस्पृ 'प्रणय' तथा राष्ट्रीयता का समन्वय असंभव है। इस दृष्टि से कांगड़ा के लोक गीत अपवाद कहे जाएंगे।

2. आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कांगड़ा के सूरमाओं की जीविका हेतु प्रदेश की अंचलिक मनोहरता से प्रवास लेकर जीवन के रागात्मक परिवेश में वियोग सहना पड़ता है।

सचमुच जिसका पैसा है, सभी उसी के हैं। पैसा देकर इस संसार में कौन सा असंभव कार्य नहीं करवाया जा सकता? यह तो दैनिक व्यवहार की वस्तु है। भौतिक ऐश्वर्य है। जो नारी पति-प्रेम को भौतिक-ऐश्वर्यों से बढ़-चढ़ कर समझती है, वह धन्य है, समाज के लिए अनुपम आदर्श है।

3. कांगड़ा-लोक गीतों में सैनिक की वियोगिनी पत्नी को

प्रिय के संयोग की स्मृतियां झकझोरती हैं, मरती हैं। विरह-वेदना का रुदन-स्वर गीत की कड़ी के रूप में पर्वत की गूँज बन-बन कर घाटियों में गूँज उठता है:—

“नामा कटाई घरै आई जाओ”

गवरु (युवक) को आर्थिक परिस्थियों ने भरती होने के लिए विवश किया है। चंद एक चांदी के सिक्कों के लिए बेचारे को अपनी गांव की ममता तथा नवेली की यौवनजन्य कोमल अभिलापाओं को दबोचने के लिए विवश होना पड़ा है। नवेली का विरह इसी के लिए सुखरित हो रहा है। नवेली अनेक फौजियों को उजले वस्त्र धारण किए आते जाते देखती है। उसे लगता है कि उसके पति की वेश-भूषा मैली होगी। इसलिए वह गांव नहीं आता। असह्य वियोग वेदना में बस उसकी एक आर्त पुकार है, उसकी एक ही रट है—प्रिय तुम नाम कटवाकर घर आ जाओ, घर आ जाओ, आ जाओ न एक बार

होरनों सपाईयों दे, चिट्टे-चिट्टे कपड़े

तूं कैजौ कीता मैला भेस, ओ सपाईया...नामा कटाई...

आखिर वह तड़फे भी क्यों न ? गांव का प्रधान जमीदार उसे सुख से जीने दे तब न। दूर खड़ों के उस पार नालों (घाटी) में कहीं पानी बहता है जमीदारों की जमीन में। निर्मम जमीदार उसे पीने के लिए पानी तक नहीं भरने देते। पानी भी जिसे नसीब न हो सके उसकी अन्तर्पीड़ा कैसी होगी भला ? गीत की दूसरी कड़ी में यही शिकवा है:—

लम्मे-लम्मे सफरे, नाले दा पानी ओ,

पीण नीं दिन्दे जमेदार, ओ सपाईया

नामा कटाई घरै आई जा ओ...।

फौज का जीवन कठोर तो होता ही है।

5. नायिक अपनी आंखों के सामने पति को 'तत्ता बात' (कप्ट) नहीं लगने देती थी। वह जान गई है कि नौकर पराधीन होने हैं। अफसर तथा नौकर के जीवन-स्तर में व्यावहारिक स्तर पर बड़ा अंतर होता है। सामान्य सिपाही तो कच्ची मिट्टी की सीलन-युक्त वैरकों में और ऊचे पद वाले अफसर लोग आलीशान पवके मकानों में रहते हैं। अफसरों को सुख से जीने की सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उनका जीवन ऐश्वर्य सम्पन्न होता है। सामान्य सिपाहियों का चिलचिलाती धूप में परेड करते समय पसीना निकल जाता है। यह कष्ट अफसरों को नहीं सहना पड़ता वे तो मात्र 'कांशन' फरमाना जानते हैं:—

‘कन्चियां तां वैरका सपाई साड़े रैवे।

पविक्यां च रैदे औदेदार, ओउ सपाईया।

सिकरै दपरै परेटां जे करदे,

काशन दिन्दे औदेदार, ओ सपाईया।

नामा कटाई करी घरै आई जा ओ...।

कांगड़ा के लोक-गायक छोकरों का कंठ सुरीला तो होता ही है। नायिका का पति भी सुरीला गाता था। वह अतीत के झरोखे से प्रेम-विभोर हो जाती है। अतीत की स्मृतियां उसे सिहरा कर रह जाती हैं। प्रिय के सुरीले कंठ के संगीत ने तो उसके मन को ही मोह लिया था। सौन्दर्य भरा यौवन और चढ़ती हुई अपनी वय पर कटाक्ष करती हुई गा-गा कर अपनी वियोग-वेदना की अभिव्यक्ति देती है... हे प्रिय। जीवन के इस चरण पर मुझे यहां प्रवास-पीड़ा देकर तुम्हें विदेश नहीं जाना चाहिए था :—

‘त्रिया मन मोहया, तेरे गले दिया गाणियां।

छड़ी नेई हा जाणा, असेगी भर जुआनिया।’

इस अवस्था में सैनिक की पत्नी को आंसुओं की माला पिरोकर ही जीवन के क्षण व्यतीत करने पड़ते हैं। वह अनपढ़ है। प्रिय को पत्र लिखवाने के लिए उसे पढ़े-लिखे लोगों की शरण में जाना पड़ता है, लाख खुशामद करनी पड़ती है, पर भाग्य की विडम्बना नियति का खेल, दुर्भाग्य उसका पीछा करने में एकदम आगे है। गांव में पढ़ा लिखा कोई हो तब न पटवारी के सिवाय। वह उसकी सौ-सौ मिन्नतें करती है पर वह पत्र लिखता नहीं, पर-पीड़न रस के कारण क्या! दुःखी को और दुःख पहुंचाने में कई बार बड़ा मजा आता है। विवश होकर कहती है—तेरा मंदा (विरह) सताता है :—

‘खत पटवारी मिकवी लिखी नियों दिदा।

सौ-सौ करनियां छन्दा, तेरा लगदा मंदा।’

आखिर इस विपन्नावस्था में करे भी क्या? शब्दों से तो नहीं पर चित्रकारी के आधार पर अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करती है। दक्षिणी हवा उससे बैर चुकाने पर उतारू हो जाती है। हवा का झोका आता है और हाथ के कागज को फड़-फड़ उड़ा ले जाता है। कलम वहीं खो जाती है।

दक्षणे दी झुलदी बाती ओ—

हत्यां दे कागद फर-फर उड़दे

कलमां गईयां न गुआची ओ।’

आखिर जैसे तैसे पत्र लिखा गया तो समस्या है पोस्ट करने की। पुराने जमाने में पक्षी हरकारे थे। मुश्किल तो यह है कि इस विरहिणी का पत्र ले जाने के लिए कोई ‘खग’ भी तो अपनी संज्ञा सार्थक नहीं करना चाहता। ऐसी दशा में पत्र भेजा भी जाए तो किसके हाथ :—

‘कुदे हत्थ भेजां सुख वे संदेसङ्गा,

कोई पखेरु की नई जांदा

तेरा लगदा मंदा।’

एक और वियोग-वेदना का अपार असीम सागर और दूसरी और उस पार जाने की अभिलाषा। पत्र में यही लिखती है—नजर सं ओझल मत होना, सामने ही रहना, विरह तो क्षण भर के लिए भी सह्य नहीं है :—

‘लिखी-लिखी राजेगी पान्दीए

मेरे राजा जी बड़ी दूर नेई जाणा

फिरदे, टुरदे सड़ी नजरां चरेण।’

आम पक्ने पर वह पत्रों से प्रिय को सूचित करती है, घर आ जाओं, पर पति देव को छुट्टी मिले तब न। उत्तर है साहब छुट्टी ही नहीं देता भला आये तो आये कैसे :—
लिखों-लिखी चिट्ठियां पा लोचणिये।

साहब छुट्टी नां दिदा क भलिये लोकणिये।’

इस पर वह मां के मरने का उल्लेख करता है। उत्तर मिलता है—अच्छा हुआ चौंका खाली हुआ तूं घर की प्रधान बन गई। ‘वह फिर लिखती है’ भाई (देवर या जेठ) भर गया है। उत्तर आता है—‘यह बहुत बुरा हुआ, मेरी तो बांह ही मानो टूट गई अब तो घर आना तभी संभव होगा जब यह साहब मरेगा :—

‘लिखी-लिखी चिट्ठियां पां बलोचनिवें।

साहब मुआ तां घर औणा, के भलिये लोकणिये।’

जब प्रिय के कुशल क्षेम का पत्र आता है, वह फूली नहीं समाती। ‘आखों में आनन्दाश्रु उमड़ने लगते हैं ‘वह पत्र को बार-बार किसी से पढ़वाती है, उसे अपनी छाती से लगा लेती है और बस रोती ही रोती है। अनुभावों का कितना मार्मिक चित्रण है।

खत मेरे सज्जणा दा आया हो,

खत में पढ़ांदी सीने कने लांदी,

नैना भरी-भरी रोंदी ओ।’

लोक जीवन की ऐसी अनुभूतियों का चित्रण विहारी ने भी किया है :—

‘कर लै चूमि, चढ़ाई सिर, उर लाई भुज मेटि।

लहि पाती पिय की लखति, वांचति धरति समेटि।’

एक लोक गीत में सैनिक की पत्नी का कहना है मेरा सिपाही पति विदेश में बड़े-बड़े बाग बगीचे लगाता है। मैं उनकी याद में अपने ही आंगन में छोटी-सी क्यारी बना कर ‘मरुआ’ के बूटा लगा लेती हूं। मेरा सिपाही दुनाली बन्दूकें लेकर आता है, मैं पत्थरों से बने अस्त-शस्त्र अपने पास रखती हूं। मेरा सिपाही अच्छे-अच्छे कुओं पर नहाता है, मैं छल्पड़ों के पानी में ही नहा लेती हूं। मेरा सिपाही तो बड़े-बड़े दरबारों-महलों में रहता है, मैं अपना जीवन खुले आसमान के नीचे पड़ी-पड़ी गुजारती हूं। मेरा सिपाही तो आलीशान लेफों तथा रजाईयों में सोता है, मैं तो जमीन पर पांद (चटाई) बिछा कर ही समय गुजार देती हूं। मेरा सिपाही लंबी अवधि के लिए नौकरी करने जाता है। मैं मन मार कर सोई रहती हूं, अवधि गिनती-गिनती समय विताती हूं।

‘लम्मियैं तरीकैं सपाई साड़े जान्दे,

सूंक ओ सुट्टी मैं सेई रैन्ती आं।’

गीत का मूल भाव यही है कि सैनिक की पत्नी, पति के सुख को अपना सुख समझती है। वह अधिक से अधिक कष्टमय जीवन जीना चाहती है। वह जानती है कि उसके पति के जीवन में अनेक कष्ट आते होंगे। वह अपने पति को प्राप्त होने वाले

सुख से अधिक सुखी नहीं होना चाहती। भारतीय लोक जीवन की नारी इस उदात्त चरित्र को लेकर ही कविवर जयशंकर प्रसाद के मन में—नारा तुम केवल श्रद्धा हो, का भाव उमड़ा होगा।

एक लोक गीत में सैनिक की पत्नी जम्मू के राजा को पत्र लिखती है कि मेरे पति को घर छुट्टी भेज दे। राजा प्रत्युत्तर में लिखता है मैं कैसे भेजूँ। सीमा पर लड़ाई लगी ढुई है। मैं तुझे जीवन यापन हेतु खर्च भेज देता हूँ आराम से खाये जा :—

‘जम्मू दिया राजिया
तू नौकरां जो घरैं घल्ल ।’
‘नौकरां जो किजां घल्ला
नेड़े लगी जो ए लाम
तलबा तिज्जो घल्ली दित्ता
सुत्ती बैठी नै खा ।’

एक लोक गीत में जर्मन की लड़ाई का भी उल्लेख है। चत्तरु नामक सिपाही को उसकी पत्नी लड़ाई के लिए भेजती है।

सैनिक तथा सैनिक पत्नी के जीवन के वियोगात्मक क्षणों का मार्मिक चित्रण कांगड़ा लोकगीतों में भरा पड़ा है। सैनिक की भी अपनी सीमाएं हैं। पत्नी शान्त चित्त से सोचती है, विवेक से काम लेती है। वह अनुभव करती है कि उसका पति इंद्रियों पर तैनात है। कैसी अनोखी नौकरी है। उसका पति देश-प्रेम-कर्तव्य का पक्का है फौज में भर्ती होते समय उसने देश-रक्षा की जो प्रतिज्ञा की थी, वह उसी को निभा रहा है :—

‘विच रैजरिया चढ़न कड़ाईयां
कस्सियां न कमरां ते करन लड़ाईयां ।
विच रजौरिया लगी ऐ हाकड़ी ।
किंजा बणाई रामा जंगे दी चाकरी ।

तू तां सपाई अपणे वचने दा पक्का, अपणे कौले दा पूरा । जब सिपाही छुट्टी पाकर घर आता है तो उसकी पत्नी सर्वप्रथम पूछती है। आपने किसको पूछ कर अपना नाम फौज में लिखवाया था :—

‘कुसी पुच्छ ए तू नामा लो आया
की बसरे रेण वालिया ।’

वह उत्तर देता है—मां को पूछ कर। तुझे तो अपने पीहर में ही रहना है अर्थात् जैसे पीहर में रह ली वैसे ही सुसुराल में :—

‘माता पुच्छ मैं नामा लोआया ।
तै मापेआं दै रैणा जिन्दिये ।’

और इस उत्तर के प्रहार से उसका प्रेमी हृदय आत्मीय भाव से चीत्कार कर उठता है :—

‘माता तेरीजा जो दाम प्यारे
मिजों तेरी जान नोकरा ।’

मां को सचमुच धन ही प्रिय है, पुत्र की जान नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता। मां की अपनी विवशताएं हैं। जब-जब सैनिक नौकरी के लिए परदेश गमन करता है, पत्नी की आखें तर हो जाती हैं। वेदना के आंसू उमड़-उमड़ कर वहने लगते हैं। उसका रेखमी चीर (रुमाल) भीग जाता है। दिन बीतते हैं। जब कभी वह कपड़े धोने लगती है, छम-छम रो उठती है और सास को उलाहना की भाषा में कहती है—“तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, कलेजा बड़ा पक्का है जो तुमने अपने पुत्र को परदेश में कमाने के लिए भेज दिया है :—

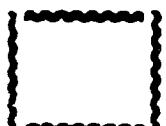
‘सैलिया घारां पौन फुहारां, मेरा रेखमी चीर सिजेया ।
चीरेगी घोनियां, छम-छम रोनियां,
सज्जण परदेसें गी तोरेआ ।
सस्तु जी धन तेरा जिगरा, धन तेरा कालजा
पुत्र परदेसें की तोरेया ।’

और सास का उत्तर है—नूहें (पुत्रधूं) पुत्र को भेजते समय [वियोग पीड़ा से] मेरा कलेजा जल जाता है, मेरा जिगर भुन्न जाता है। क्या करूँ रुपयों की लालच से भेजा है उसे :—

‘नूहएं ओ जली जान्दा कालजा, भूजी जांदा जिगरा—
दमों दै लालचैं तोरिया ।’

आर्थिक कठिनाइयों अभिशाप बन गई है। स्पष्ट है कि कांगड़ा के लोक गीतों में प्रणय तथा राष्ट्र प्रेम के भावमिश्रित है। पत्नी वियोग-सागर में सराबोर है। एक ओर सूरमा वीर अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं और दूसरी ओर फूल-सी कोमल, गंगा जल-सी पावन, कोमल प्रणय-पुतलियों के हृदय की विरह भावनायें प्रेम की सात्त्विकता भरे हुए यौवन की प्रणय भावनाएं फूट-फूट कर वह रही हैं। सचमुच कांगड़ा के ये लोक-गीत ज्ञाने की सी प्रकृति वाले हैं जिनकी रसधारा का प्रवाह कभी थमता नहीं। भाव-पक्ष की इस अनूठी सम्पदा का कोई मूल्य चुका सकता है? नहीं कभी नहीं।

मनोहर लाल
बी-71 अशोक बिहार
दिल्ली-32



स्ट्रेटरी

काली छाया ★ डा० कृष्ण मुरारी शर्मा 'उन्निद्र'

पात्र :

डा० दयाराम ; एक चिकित्सक ; मोहन सिंह ; एक शिक्षक राम ; मोहन का लगभग पांच वर्षीय लड़का पुत्र ; श्यामू ; मोहन सिंह का लगभग आठ वर्षीय स्वस्थ पुत्र ; लीला ; दो वर्षीय रोगी बालक दिनेश की माँ ; सेठ खूब चंद ; एक रोगी ; चपरासी ; डा० दयाराम का भूत्य।

(सामने ही एक बोर्ड पर लिखा है—‘डा० दयाराम का अस्पताल’। ठीक सामने डा० की कुर्सी के ऊपर दीवाल पर लिखा है—‘जन सेवा ईश्वर की सेवा है। वायीं ओर के द्वार पर ‘वेटिंग रूम’ की तस्वीर लगी है और दायीं ओर ‘इंजैक्शन तथा औषधि वितरण कक्ष’ लिखा है। चिकित्सालय की अन्य दीवारों पर मानव शरीर सम्बन्धी कुछ चार्ट्स भी टंगे हैं। वेटिंग रूम के दरवाजे पर स्टूल डाले चपरासी बैठा है।)

डा० दयाराम : (सामने टेबल पर क्रम से रखे पर्चों में से एक-एक को उठाकर सेठ खूबचंद को बुलाओ।)

चपरासी : वेटिंग रूम की ओर मुंह करके नाम पुकारता है—सेठ खूबचंद। (भारी-भरकम शरीर वाला एक व्यक्ति वेटिंग रूम से निकल कर डा० दयाराम के कमरे में प्रवेश करता है।)

सेठ खूबचंद : हाथ जोड़कर—नमस्ते, डाक्टर साहब।

डा० दयाराम : नमस्ते ! बैठिए।

(सेठ खूबचंद डाक्टर के निकट रखे स्टूल पर बैठता है।)

डा० दयाराम : (सेठ खूबचंद की तौंद पर हाथ फिराकर) कहिए सेठ ! क्या हाल है ? अभी तुम्हारी बादी घटी नहीं। (नब्ज देखते हुए) कल बुखार तो नहीं आया ? नाड़ी तो ठीक चल रही है। पर… (योड़ा रुक कर) हां कल बुखार तो नहीं आया ?)

सेठ खूबचंद : नहीं साहब ! बुखार तो तीन-चार दिन से नहीं आया। बस, थोड़ी कमज़ोरी……

डा० दयाराम : हां भाई ! ये ही तो असली बीमारी है तुम्हें। घबराओ मत सेठ। ठीक करके छोड़ूँगा। (कानों पर स्टेथिस्कोप चढ़ा कर मरीज की छाती पर दो-एक जगह लगाते हुए) हां सांस लो—जोर-जोर से।

(सेठ जोर-जोर से सांस लेता है जिससे उसके बड़े पेट का उतार-चढ़ाव साफ दिखने लगता है।)

डा० दयाराम : कानों से स्टेथिस्कोप उतार कर) सेठ जी ! बड़ी खतरनाक बीमारी है।

सेठ खूबचंद : (एकदम घबराकर) ऐ… (आँखें फाड़े रह जाता है।)

डा० दयाराम : घबराओ मत। बस, कुछ इंजैक्शन और लगेंगे। खाओगे-पीओगे तो जलदी ठीक हो जाओगे। समझे। (रुखाई के साथ) बढ़ाओ आज के पांच रुपए।

सेठ खूबचंद : (भीतर वाली जेव से बीस रुपए का एक नोट निकाल कर लीजिए साहब)

डा० दयाराम : अरे ! ये तो बीस रुपए का नोट है। (मुस्करा कर) अच्छा, तो ठीक है, आज के अलावा, तीन दिन के इंजैक्शन की फीस और जमा किए लेता हूं। समझे न। (टेबिल के ड्रावर में नोट डाल कर) तुम्हारी फीस आ गई, नोट किए लेता हूं। पर्चे पर कुछ लिखता है।

सेठ खूबचंद : पर साहब मैं तो इन सुझियों से तंग आ गया हूं। मुझे अब एक भी सुई नहीं लगवानी। (बांहों पर हाथ फेर कर) मरा जाता हूं, दर्द के मारे। हाथ जोड़ता है। कोई दवाई हो तो दे दो।

डा० दयाराम : नहीं-नहीं, पूरा कोर्स हो जाने दो। रोगी को पूरी तरह ठीक न होने पर डाक्टर बदनाम होता है। समझे। जाओ इंजैक्शन लगवाओ। (सेठ खूबचंद अरुचिपूर्ण ढंग से इंजैक्शन कक्ष में चला जाता है। तभी मोहन सिंह अपनी पीठ पर अपने रोगी पुत्र रामू को लादे हुए अस्पताल के सामने रुकता है। रोगी काले कम्बल से ढका है। मोहन सिंह हाँफ रहा है। उसके साथ उसका द्वितीय पुत्र भी है।)

मोहन सिंह : (चिकित्सालय में प्रवेश कर रोगी पुत्र को सभाल कर उतारते हुए) श्यामू सहारा दे।

श्यामू सहारा देता है, किन्तु वह अपने रोगी भाई को संभाल नहीं पाता। तब दोनों मिल कर उसे

		वहाँ धरती पर लिटा देते हैं।
मोहन सिंह	: (निवेदन करते हुए) डा० साहब। जरा जल्दी करिए। बच्चे की बहुत गंभीर हालत है।	(मोहन सिंह मरीज को वेटिंग रूम में ले जाता है। श्यामू उसके पीछे-पीछे जाता है। चपरासी अपने स्टूल पर फिर बैठ जाता है।
डा० दयाराम	: (लापरवाही से) जल्दी-बल्दी कुछ नहीं। हम अपने मरीजों को नम्बर से देखते हैं। दिखाना है तो, कम्पाउण्डर के पास जाओ और पर्चा बनवाओ। नम्बर आने पर बुला लिया जाएगा। समझे।	डा० दयाराम : (पचें उठाकर) हाँ, दिनेश, लीला के पुत्र को बुलाओ।
मोहन सिंह	: (याचना के स्वर में) दया करिये, डाक्टर साहब! बच्चे की हालत बहुत खराब है। थोड़ी देर भी…	चपरासी : (नाम पुकारता है) दिनेश, लीला का पुत्र। (सफेद साड़ी पहने एक तरुणी प्रवेश करती है। उसकी गोद में उसका दो वर्षीय पुत्र है।)
डा० दयाराम	: (निश्चित मुद्रा में) हम क्या करें। तब से क्या सो रहे थे। अब हम इसे इमरजेंसी केस के रूप में देख सकते हैं, पचास रुपए देने पड़ेंगे और दूसरा खर्च अलग होगा। लाए हो गेंसे?	लीला : (मुस्कान महिला) नमस्ने, डाक्टर साहब।
मोहन सिंह	: (दैन्य प्रकट करते हुए) नहीं साहब। मेरे पास तो बस बीस-पच्चीस रुपए होंगे। पर, आप चिन्ता न करें, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं आपकी कौड़ी-कौड़ी चुका दूँगा।	डा० दयाराम : नमस्ते।
डा० दयाराम	: (खाइ के साथ) यहाँ उधारी का काम नहीं। कोई और डाक्टर ढूँढ लो।	लीला : (खड़ी रह कर ही अस्वस्थ बच्चे को दिखाते हुए) इसे डाक्टर साहब…
मोहन सिंह	: छोटी जगह है, डाक्टर साहब। इस समय यहाँ और कोई अच्छा डाक्टर नहीं है। आप ही मेहरबानी करिए। डाक्टर तो भगवान का रूप होता है।	डा० दयाराम : (बीच में ही) अरे! यहाँ बैठिए तो। (स्टूल की ओर सकेत करता है।) ऐसे खड़े-खड़े कहीं बात की जाती है। (लीला स्टूल पर बैठती है और बच्चे को अपनी गोद में लिटा कर डाक्टर की ओर किए रहती है। डाक्टर लीला के सुन्दर मुख पर आंखें गढ़ देता है। बच्चे की ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए वह लीला की ओर देखता ही रह जाता है।)
डा० दयाराम	: ठीक है-ठीक है, मेरा वक्त खराब मत करो। रुपए हों, तो बात करो।	लीला : (खिन्न होकर) डाक्टर साहब! बीमार मैं नहीं हूँ, मेरा बच्चा बीमार है। मुझे नहीं, इसे देखिए।
मोहन सिंह	: (अधीर होकर) रुपए नहीं हैं, डाक्टर साहब। मैं शिक्षक हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी देर में ही कहीं न कहीं से लाकर आपके रुपए दे दूँगा। आप हों कृपा करके इसे देख लीजिए। (डाक्टर के पैर पकड़ कर) डाक्टर साहब। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डाक्टर साहब।	डा० दयाराम : (उत्तेजित स्वर में) एक अपरिचित महिला से इस प्रकार हंसी-मजाक करने में आपको हिचक नहीं होती? अगर आप भले आदमी की तरह बच्चे का इलाज कर सकें, तो कीजिए। खड़ी होती है।
डा० दयाराम	: (पैर छुड़ाकर) तुम्हारे पास रुपए नहीं हैं, तो ले आओ किसी से। मैं मरीज को तभी देख सकूँगा, अपना नियम नहीं तोड़ सकता। (भृत्य से) चपरासी। इन लोगों को वेटिंग रूम में पहुँचाओ।	लीला : अरे! बैठिए—बैठिए। (लीला फिर बैठ जाती है।)
चपरासी	: जी साहब। (मोहन सिंह से) मरीज को उठा लो और इधर ले आओ। उसे यहाँ बैच पर लिटा कर रुपए ले आओ।	डा० दयाराम : (अत्यन्त मुश्किल वाणी में) लीलाजी! इसमें गुस्से की क्या बात है? मैंने किया ही क्या है? आप को बस पहचान ही तो रहा था। खैर, छोड़िए (धीमे स्वर में) एक बात कहूँ?
मोहन सिंह	: (उदास होकर) अच्छी बात है। ईश्वर की मरजी (रामू को गोद में उठाकर) श्यामू! तू इसके पास बैठना। मैं दीपचंद से कुछ रुपए उधार लिए आता हूँ। देख! ध्यान रखना। कोई बात हो, तो तुरन्त डाक्टर साहब को बतला देना।	लीला : हाँ-हाँ कहिए।
श्यामू	: (सहमति में सिर हिला कर) अच्छी बात है।	डा० दयाराम : (एक विचित्र मुस्कान के साथ) बुरा न मानिए, लीलाजी! आप गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हैं।
		लीला : (क्रुद्ध स्वर में) डाक्टर! यह निर्लज्जता अच्छी नहीं। मैं…(अचानक तभी वेटिंग रूम से श्यामू का करुण स्वर सुन पड़ता है—‘भैया-भैया’—वह दौड़ता हुआ डाक्टर के पास पहुँचता है।)
		श्यामू : (घबराहट के साथ) डाक्टर साहब! मेरे भैया

को कुछ हो गया है। भैया की आंखें सफेद हो गई हैं। आप चल कर.....

डा० दयाराम : (कठोरता पूर्वक) अबे पिट्ठी ! हो जाने दे। तेरा बाप तो अभी तक नहीं लौटा। उसे आने दे पहले। हम अभी आते हैं। (हाथ से संकेत करते हुए) चल वहां जा।

(श्यामू अत्यन्त दैन्य भरी दृष्टि के साथ कभी डाक्टर को, तो कभी लीला को देखता है और किर चुपचाप वेटिंग रूम में चला जाता है।)

लीला : (निवेदन के स्वर में) उस बच्चे को देख लीजिए। डाक्टर साहब। बहुत सीरियस मातृम होता है। मेरे बच्चे को बाद में देख लीजिएगा।

डा० दयाराम : (प्रसन्न होकर) अच्छा, तुम कहती हो तो... (तभी वेटिंग रूप में मोहन सिंह का स्वर सुन पड़ता है—'श्यामू ! मैं रुपए ले आया।' श्यामू कुछ कह पाये इसके पूर्व ही पसीने में लथ-पथ मोहन सिंह डाक्टर के सामने पहुंच जाता है।)

मोहन सिंह : (जोर-जोर से हांपते हुए) लीजिए डाक्टर साहब ! (सी रुपए का एक नोट टेबिल पर रखते हुए) ये रही आपकी फीस।

डा० दयाराम : (नोट ड्रावर में डाल कर ऊपर उदारता दिखाते हुए) चलो, वहाँ देखे लेता हूँ। यहां उठा कर लाने में बच्चे को कष्ट होगा। (लीला से) आप तब तक बैठिए।

मोहन सिंह के साथ स्टेथिस्कोप हाथ में लिए डाक्टर दयाराम ज्योंही वेटिंग रूम में प्रवेश करता है, त्योंही लीला अपने बच्चे को लेकर बाहर चाले रास्ते से घर चली जाती है। कुछ ही देर में डा० दयाराम अपने कक्ष में लौट आता है। मोहन सिंह जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखते हुए उसके साथ-साथ चलता है। डाक्टर अपनी कुर्सी पर बैठता है। मोहन सिंह व्यग्रतापूर्वक उसके मुख की ओर देख रहा है।)

डा० दयाराम : बैड लक, मुझे खेद है, मोहन सिंह। अब कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत देर कर ली।'

मोहन सिंह : (पागलों के समान आंखें फाड़े हुए) डाक्टर...! मेरे बच्चे को बचा लो, डाक्टर ! मेरे बच्चे को बचा लो। डाक्टर। ये अहसान कभी नहीं भूलूंगा, डाक्टर ! (हाथ जोड़ता है। तुम्हें ईश्वर की सीधगन्ध है डाक्टर। बचा लो डाक्टर। (पैरों पर गिर पड़ता है।)

डा० दयाराम : (पैर छुड़ाते हुए) वैरी सौरी। अब कुछ नहीं

हो सकता।

मोहन सिंह : (व्याकुल होकर) ऐ.....ऐ.....व...व...क...क्या ?

डा० दयाराम : हां, वह इस लोक से जा चुका है। आप उसे उठा ले जाइए।

मोहन सिंह : (एकदम चीखते हुए) डाक्टर ! मेरे बच्चे को तुमने मारा है—तुमने। (उंगली से इशारा करते हुए) उसके हत्यारे तुम हो। तुम

डा० दयाराम : (डांटते हुए) बेवकूफ कहीं का। हट यहां से। उठा ले जा उस कूड़े को।

मोहन सिंह : (उत्तेजित होकर मुट्ठियां बांधते हुए) मैं तेरा खून कर दूंगा। (दांत पीसते हुए) मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। उस सफेद दर्पण को तोड़ डालंगा जिसमें अपनी काली छाया छिपाए हुए हैं। (क्रोधित मोहन सिंह डाक्टर की ओर लपकता है।) चपरासी बलपूर्वक उसे रोक लेता है।)

डा० दयाराम : (कठोरतापूर्वक) मारटर ! आपे में रह। जेल तो नहीं जाना ?

मोहन सिंह : (दांत पीसते हुए) तेरा खून पीकर जेल भी चला जाऊंगा ? नीच ! (चीखता है) दयाराम नाम रख लिया है, पर दया का नाम भी नहीं जानता। दयाराम नहीं, दुष्टराम। मेरे बच्चे के हत्यारे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।

(उत्तेजित होकर मोहन सिंह फिर डाक्टर की ओर बढ़ता है, किन्तु चपरासा उसे फिर रोक लेता है। फिर भी आंखों से अंगारे बरसाते हुए डाक्टर की ओर देखता रहता है।)

डा० दयाराम : (ड्रावर से सी रुपए का नोट निकाल कर मोहन सिंह की ओर फैकते हुए) ले, अपने रुपए ले और हट यहां से, वरना.....

मोहन सिंह : (क्रूद्ध दृष्टि से डाक्टर को देख कर जोर से चिल्लाता है) खूनी। धमकी देता है। मैं..... (तभी वेटिंग रूम से श्यामू का रुदन भरा स्वर सुनकर वह एकदम अदीर होकर वेटिंग रूम की ओर देखता है। श्यामू रो रहा है और कह रहा है—'भैया ! मेरे भैया ऊँ...ऊँ...ऊँ...भैया !' व्याकुल होकर मोहन सिंह वेटिंग रूम में प्रविष्ट होता है।)

(यथनिका धात)

—शासकीय महाविद्यालय,

मुरार,

ग्रालियर-6 (म०प्र०)

गोबर-गैस संयंत्र के समाचार

खरपतवार नियंत्रण

केन्द्रीय कृषि एवं सिचाई मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खरीफ मौसम के दौरान खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यक्रम लागू करने की सलाह दी है। चावल को पंक्तियों में बोने और खरपतवार को आरंभ में ही हटाने की सिफारिश की गई है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

भूमि को उचित रूप से खेती योग्य बनाने और चावल को छितराने के स्थान पर कतारों में लगाने को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिए उन्नत साधनों का प्रयोग कर खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन करने का कार्यक्रम असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इस वर्ष भी चालू रहा है। इस कार्यक्रम को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है जहां चावल को छिट्ठा-वपिन्द्र से बोया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने हर प्रकार की फसलों के लिए उचित टैक्नोलॉजी अपनाने पर भी बल दिया है। राज्य सरकारों को चावल की उचित समय पर बुवाई और उचित किस्म के चयन करने के लिए भी आग्रह किया गया है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। राज्य सरकारों को 92 लाख रुपए से अधिक उपलब्ध कराया गया है ताकि वे सरकारी और जहां सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों वहां सामुदायिक नसंरियां लगा सकें।

गोबर-गैस संयंत्र

चालू वर्ष में गोबर-गैस संयंत्रों के लगाने के लिए आर्थिक सहायता देने में अपेक्षाकृत अधिक उदार नीति अपनायी गई है। इस प्रकार छोटे किसानों और जन-जातीय क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सकेगा। 2 और 3 घनमीटर के गोबर-गैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता कुल पूँजी लागत की 25% होगी और दूसरे आकारों के संयंत्रों के लिए यह सहायता कुल पूँजी लागत का 20% होगी। पहाड़ी और जन-जातीय क्षेत्रों के लिए यह आर्थिक सहायता सभी आकारों के संयंत्रों के लिए कुल पूँजी लागत का 50% होगी।

सभी राष्ट्रीय कृषि बैंक गोबर-गैस संयंत्र लगाने के लिए ऋणों के रूप में सहायता दे रहे हैं। हाल ही में, कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम ने बैंकों को सहायता देने की मंजूरी दी है। योजना के अधीन 2, 3 और 4 घन मीटर के संयंत्रों के लिए ऋण की बदायगी 7 वर्षों में की जा सकती है। ऋण लेने वाले को कम दर पर ब्याज देना होगा, जबकि बर्तमान में 11% सालाना है।

आरंभीय रिसर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को सलाह दी है कि वे गोबर-गैस संयंत्र लगाने वालों से उसी दर पर ब्याज वसूल

करें जो स्वीकृत मध्यकालिक प्रस्तावों के ऋणों पर लेते हैं।

गोबर-गैस संयंत्र से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छा उर्वरक उपलब्ध होता है और साथ-साथ गैस भी प्राप्त होती है जो खाना पकाने, बिजली और ढीजल इंजन चलाने में काम आती है। इसके अन्य लाभ हैं—बेहतर सफाई, बनों का बचाव और जन घंटों की बचत। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश में गोबर-गैस संयंत्र चालू करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। योजना वर्ष में एक लाख गोबर-गैस संयंत्र चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। 1974-75 और 1975-76 में 20,000 गोबर-गैस संयंत्र बिठाने का अभियान शुरू किया गया। किसानों द्वारा गोबर-गैस संयंत्र लगाने में रुचि न लेने के कारण, केन्द्रीय कृषि एवं सिचाई मंत्रालय ने योजना अवधि के दौरान, गोबर-गैस संयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। किसानों ने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई और 1976-77 के अन्त तक 45,000 गोबर-गैस संयंत्र लगाए। वर्तमान आर्थिक सहायता की नीति को उदार बनाने का मुख्य उद्देश्य गोबर-गैस संयंत्रों को लगाने के लिए बढ़ावा देना है।

खादी ग्रामोद्योग

उद्योग मंत्री ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस वर्ष के योजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग के लिए अनुदान और ऋण के रूप में 35 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस राशि में व्याज सहायता भी शामिल है। इस 35 करोड़ रु० की राशि में से खादी उद्योग को 7·40 करोड़ रु० अनुदान और 10·70 रु० ऋण के रूप में दिए गए हैं। ग्रामोद्योग को 2·40 करोड़ रु० अनुदान और 6·10 करोड़ रु० ऋण के रूप में दिए गए हैं। ऋण राहत के रूप में 8·40 करोड़ रु० की राशि दी गई है।

मंत्री महोदय ने यह जानकारी भी दी कि ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं और ग्रामीण दस्तकारी कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष के बजट में अनुदान और ऋण के रूप में 4·40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। उद्यमियों को बीजों और सीमांत धन के लिए अनुदान और ऋण देने के लिए 6 करोड़ रु० रखे गए हैं। इस राशि का कुछ भाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए भी उपलब्ध होगा।

ग्रामीण विकास

पिछले सप्ताह बैंकाक में ग्रामीण विकास प्रोद्योगिकी के लिए समन्वित दृष्टिकोण पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन एशियाई

प्रौद्योगिकी संस्थान और कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने मिलकर किया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ए० एस० चीमा ने सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों को एशिया में ग्राम विकास के लिए समन्वित अयोजन के क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने का मौका उपलब्ध कराना था।

डा० चीमा ने सम्मेलन में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं विषय पर एक लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने स्थानीय ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीब वर्गों की सहायता की दृष्टि से विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया। इस सम्बन्ध में उनके सुझाव स्वीकार कर लिए गए।

तिलहनों की पैदावार

भारत सरकार को मूँगफली,, तोरी और सरसों की खेती

वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र समर्थित योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विज्ञान की उन्नत विधियों की, जिनमें उत्तम किस्म के वीजों का इस्तेमाल करना, उर्वरकों का उपयोग तथा पौधों आदि के कीड़ों से बचाव शामिल है, लोकप्रिय बनाना है। खेतों में प्रदर्शन-आयोजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने को भी इस योजना का अंग माना गया है।

असिचित क्षेत्रों की तुलना में निचित क्षेत्रों में तिलहनों की पैदावार काफी अधिक है। फिर भी पैदावार बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है।

अखिल भारतीय तिलहन वर्कशाप तथा भारतीय तिलहन विकास परिषद् की वैठकों में नम्बद-समय पर मूँगफली और अन्य तिलहनों की पैदावार में हुई वृद्धि की समीक्षा की जाती है। भारत सरकार द्वारा हात ही में गठित एक विशेष दल ने बीज उत्पादन कार्यक्रम और मूँगफली तथा अन्य तिलहनों के पौधा संरक्षण उपायों को तेजी से लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

नयी स्वास्थ्य योजना

हमारा देश गांवों का देश है। यहां की 80 प्रतिशत आवादी गांवों में बसती है, पर वेचारे ग्रामीणों को हारी-बीमारी अवस्था में सरकार की ओर से स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं नहीं के बराबर उपलब्ध हैं। परन्तु अब हमारी नयी सरकार ने इस दिशा में पग उठाया है और श्री राजनारायण जी की नयी स्वास्थ्य योजना एक क्रान्तिकारी कदम है।

इस नयी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना और इसके साथ-साथ उन्हें बीमारियों से अपनी रक्षा करने व अच्छा स्वास्थ्य बनाने की शिक्षा देना है। इस नई योजना के अन्तर्गत एक हजार व्यक्तियों की आवादी वाले प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसे आम बीमारियों के उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण तीन महीने का होगा। पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान की मूल-भूत वाते, स्वास्थ्य अच्छा रखने के उपाय, आरोग्य शास्त्र, छूत की आम-बीमारियों का इलाज, जच्चा-बच्चा की देखभाल, साधारण बीमारियों का

इलाज और प्राथमिक उपचार आदि शामिल हैं। इन्हें एक बक्सा भी दिया जाएगा जिसमें आम रोगों के इलाज के लिए आधुनिक और पराम्परागत तरीकों की औषधियां होंगी। साथ में चिकित्सा सम्बन्धी एक पुस्तक भी होगी। इसके बाद काम करने के लिए उन्हें अपने-अपने गांवों में भेज दिया जाएगा।

जहां तक इस नई योजना का सम्बन्ध , एलोपैथिक डाक्टर इससे सहमत नहीं है। उनका कथन है कि इससे नीम-हकीमों की बाढ़ आ जाएगी। पर वे यह क्यों भूल जाते हैं कि आज नीम-हकीमों से ही वेचारे ग्रामीणों को हारी-बीमारी की अवस्था में राहत मिल रही है। इन नीम-हकीमों में बड़े-बड़े सुयोग्य व्यक्ति पाए जा सकते हैं। अतः हमारा श्री राजनारायण जी से अनुरोध है कि अपनी योजना के अन्तर्भृत वे इन नीम-हकीमों को भी प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाएं भी उपलब्ध करें।

यह मानी हुई वात है कि जो आदमी जहां पैदा होता है उसके लिए वहां की जलवायी, वहां की भूमि, वहां के वातावरण में उपलब्ध औषधियां ही उसके लिए हितकर हो सकती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है :— यस्य देशस्य यो जन्तुः



तज्जं तस्य औषधं हितम् ॥ अर्थात् जो जिस देश का रहने वाला है उसे उस देश की औषधियां ही हितकर हो सकती हैं। अतः श्री राजनारायण जी, गांवों में इन तथाकथित नीम-हकीमों के पास रामबाण औषधियों की जानकारी का जो भण्डार उपलब्ध है उसके सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दें। ★

साहित्य निर्पाद्धा

भारत तुम्हारा और मेरा : लेखिका : कमला डॉगरकेरी, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 119, मूल्य : 6.00 रु

भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी किशोरों को देने के निमित्त लिखी गई इस पुस्तक की भाषा सरल-सुवोध है। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि बच्चों के लिए ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और ऐसे ही अन्य पक्षों को समझाना कोई आसान नहीं है। यही कारण है कि अपने देश की पुरानी मान्यताओं, परम्पराओं और महान आदर्शों के प्रति बच्चों में हच्छ और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयुक्त शैली में लिखी गई है और इसमें छोटी-छोटी कथाओं का सहारा लिया गया है।

भारत के नामकरण और भौगोलिक स्थिति से आरम्भ करके आधुनिक भारत के निर्माण तक लेखिका ने कुल 28 अध्याय लिखे हैं। इन अध्यायों में हमारी भाषाएं, धर्म, कला और साहित्य, प्राचीन भवन-निर्माण कला, हस्तकला-वेषभूषा आदि का वर्णन है। साथ ही, देश के त्यौहारों, खेलकूद, पशु-पक्षी, वृक्ष आदि के बारे में भी वांछित जानकारी दी गई है। फिर, वन-भारत के निर्माण में जिन महान व्यक्तियों ने योगदान दिया उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। पुस्तक में 13 चित्र हैं जो भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

कुल मिलाकर पुस्तक रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक है। छपाई-सफाई बढ़िया है, मुख्यपृष्ठ आकर्षक वन पड़ा है। विशेषकर बच्चों के लिए और प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं। हाँ मूल्य कुछ कम रहता तो अधिक अच्छा रहता। ऐसी मुन्द्र पुस्तक के लिए लेखक-प्रकाशक बधाई के पात्र हैं। ★

—त्रिलोकी नाथ (प्रोग्राम एसिस्टेंट)
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय,
ईस्ट ब्लाक 4, लेवल-3, रा० क० पुरम
नई दिल्ली-110022

योग द्वारा रोगों की चिकित्सा : (लेखक डा० पुलगंदा सिन्हा, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, प० 163, मूल्य : दस रुपए।)

रोगों से मुक्ति पाने के लिए आजकल एलोपैथिक औषधियों का प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है, जो सभीचीन नहीं है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इस पद्धति से इलाज करने पर जब एक रोग चला जाता है, तो साथ ही एक दूसरे रोग की भी किसी अंश में शुरूआत हो जाती है। अतः यह प्रणाली भारतीय जलवायु के अधिक अनुकूल नहीं है।

प्रस्तुत कृति ऐसे विविध आसनों पर प्रकाश डालती है, जो अनेक असाध्य रोगों को सर्वथा समाप्त करने में समर्थ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तक में उल्लिखित योग-आसनों का अधिकाधिक प्रचार हो। भारत में ही अपनी यह योग-साधना-पद्धति पर्याप्त प्रचार नहीं पा सकी है।

इस कृति में उदररोग, मधुमेह, दमा, सन्धि शोथ, मोटापा मानसिक समस्याओं तथा श्यरोग और रक्तचाप पर सात अध्याय हैं। इनमें चित्रों के माध्यम से रोगों को समाप्त करने हेतु आसनों, प्राणायामों आदि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिससे आरंभिक अभ्यासार्थियों को पुस्तक में उल्लिखित आसनों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

आज के व्यवसाध्य औषधिक-प्रणालियों के कारण इस पुस्तक का महत्व और उपयोगिता निश्चित ही अपेक्षित है।

पुस्तक की भाषा सरल-सुवोध है। उपयोगिता असन्दिग्ध है। अतः प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं। विश्वास है, यह पुस्तक रुग्ण तथा स्वास्थ्य जगत् दोनों को ही लाभप्रद सिद्ध होगी।

— राकेश पाठक

ए-339, सूर्यनगर,
पो० चिकम्बरपुर,

गोजियाबाद-201006।

संघ की राजभाषा : संकलन कर्ता—हरिबाबू कंसल व जगन्नाथ, प्रकाशक, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 पृष्ठ—65, मूल्य केवल 1 रु०।

भारत सरकार अपने कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक आदेश निकालती रहती है। लेकिन इन आदेशों, नियमों, अधिनियमों का समुचित रूप से अनुपालन तभी हो सकेगा, जबकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को उनकी जानकारी हो किन्तु इनका एक ही जगह संकलन न होने से इनमें से अनेक आदेशों आदि की जानकारी उनको भी नहीं होती जिनको इनकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु राजभाषा सम्बन्धी संविधान की व्यवस्थाओं और समस्त महत्वपूर्ण सरकारी नियमों अथवा नियमों को संकलित कर प्रस्तुत पुस्तिका तैयार की गई है। इसके संकलनकर्ता भारत सरकार के राजभाषा विभाग के उपसचिव श्री हरिबाबू कंसल, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के महामंत्री श्री जगन्नाथ जी हैं।

पुस्तिका के प्रथम भाग में राजभाषा के रूप में हिन्दी की वैधानिक स्थिति और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1955 तथा 1960 के राष्ट्रपति के आदेश दिए गए हैं। दूसरे भाग में राजभाषा अधिनियम 1963 (राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संशोधित) तथा भाषा नीति विषयक संसदीय संकल्प दिया गया है। तीसरे भाग में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1976 में बनाए गए राजभाषा के नियमों को लिया गया है। इन

नियमों से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी सम्बन्धी ये आदेश कहाँ-कहाँ, किस-किस सीमा तक लागू होते हैं। इनके अनुपालन में प्रशासनिक प्रधान का क्या दायित्व है। अन्तिम भाग में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधिकारियों की राजभाषा सम्बन्धी अनुदेशों के अनुपालन की निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हन्दी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी बैठकों की व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेश, हिन्दी टाइप-राइटरों की व्यवस्था आदि के आदेश दिए गए हैं। अंत में राजभाषा के प्रयोग सम्बन्धी 1976-77 का वह कार्यक्रम भी दिया गया है, जिसे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से मार्च 77 तक पूरा कर लेने को अपेक्षा की गई थी।

इस प्रकार इस संकलन के प्रकाशित हो जाने से जनता को भारत सरकार के हिन्दी सम्बन्धी समस्त आदेशों को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सही रूप में, एक ही जगह जानकारी मिल सकेगी। आशा है इससे उन सरकारी कर्मचारियों की जो अपने काम काज में हिन्दी का प्रयोग करने में हिचकिचाते या डरते थे, दिशक दूर होगी और उनके द्वारा हिन्दी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में बढ़ने लगेगा।

शशिवाला

डी-1/53, सत्यमार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

जानकी सहस्रनाम : (लेखिका : जानकी देवी बजाज, प्रकाशक; प्रशास्त्राल जैन, मंत्री, सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, मूल्य : ग्यारह रुपए, पृ० संख्या : 328।

ऋषि विनोदा की प्रेरणा से माता जानकी देवी बजाज द्वारा लिखित इस पुस्तक में उन एक सहस्र व्यक्तियों के नाम संक्षिप्त संस्मरण के साथ संग्रहीत है, जो उनके सम्पर्क में आते रहे थे। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें छोटे-बड़े का कोई विचार नहीं किया गया है। पुस्तक को पढ़कर कोई भी योड़ी

देर में अनेक ज्ञानों में कार्य करने वाले लोगों, समाज सेवियों, राजनेताओं तथा धार्मिक व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।

इस पुस्तक की भाषा बड़ी सरल है। पुस्तक में अशुद्धियां नहीं हैं। मूल्य कम है। मुद्रण समीचीन एवं आकर्षक है। इस प्रकार यह पाठकों को व्यक्तियों की जानकारी देने में नितान्त उपयोगी और पठनीय है।



—कु० आशा शर्मा
द्वारा-श्री हंसराज पहवा,
बी-१, अर्जुन मोहल्ला,
प्राइमरी स्कूल गेट के सामने
मौजपुर, दिल्ली-110053

हमारे संत महात्मा : संपादक यशपाल जैन, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, 1977, मूल्य : तीन रु०।

सुबोध साहित्य माला के अन्तर्गत प्रकाशित 'हमारे संत-महात्मा' भारत की सांस्कृतिक परम्परा की चार महान विभूतियों गुरु नानक, नरसीमेहता, चतुर्थ महाप्रभु तथा दक्षिण की मीरा (आंडाल) के जीवन चरित्र वर्णित किए गए हैं। क्रमशः उनके लेखकों—सोहन सिंह, मोहन लाल भट्ट, देवराज दिनेश तथा महेश नारायण भारती—ने अत्यन्त सरल और सुबोध शब्दों में इन महात्माओं की जीवन गाथा लिखकर भारत के सामान्य जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। महात्माओं के जीवन की मार्मिक घटनाओं का उल्लेख करके उनके चरित्रों को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ अपने रचना के उद्देश्य में पूरा खरा उत्तरता है। पुस्तक की छार्ट-साज सज्जा तथा विभिन्न चित्रों के माध्यम से पुस्तक की रोचकता और भी बढ़ जाती है। प्रकाशक इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

★—डा० ब्रज नारायण तिह
बी-२४, राम प्रस्थ कालोनी
सेक्टर-XII, पो-चिकम्बरपुर,
गाजियाबाद-201006



मुझे औरतों के काम पसंद नहीं

—देवीसिंह नरूका

राजस्थान के सीमावर्ती जिला, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील मुख्यालय, से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रंग महल के निवासी वीदावत वावरी सुखराम की पुत्री द्रोपदी को औरतों के काम पसंद नहीं हैं। इसी कारण से वह पुरुषों की भाँति रहती है और वह सब मेहनत के काम करती है जो पुरुष कर सकता है। लुंगी, कमीज और लड़कों जैसे छांटे हुए बाल देखकर कोई यह अन्दाज नहीं लगा सकता है कि यह स्त्री है किंतु 15-17 वर्ष का किशोर दिखाई देती है।

कुछ समय पूर्व जब मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार की मर्दनी औरत इस गांव में रहती है तब मैं अपने आपको वहां जाने से नहीं रोक सका। पहली बार जब गया तो दमे के रोगी उसके 50 वर्षीय पिता ने बताया कि प्रातः से ही वह सरेशियों को लेकर सूरतगढ़ फार्म के क्षेत्र में चराने के लिए ले गई है। यह भी बताया गया कि वह शादी नहीं कराना चाहती थी किंतु घर वालों ने लोक लाज के डर से दस वर्ष पहले पास के ही ग्राम में उसकी शादी कर दी। सुसुराल में एक दिन से अधिक नहीं ठहरी और माता के घर पर लौट आई। उसके बाद सुसुराल जाने से साफ इन्कार कर दिया। रंगमहल ग्राम में ही उसे एक मुरब्बा (25 बीघा) जमीन भी आवंटित कर दी गई है। वह स्वयं खेती के सब काम

करती है और वृद्ध माता पिता के काम में भी सहयोग देती है। ग्रामवासी भी उसे द्रोपदी न कहकर 'दोप्यो' नाम से पुकारते हैं। बचपन से ही उसे लड़कों की भाँति रहना ही पसंद था।

इस प्रकार से जब पहली बार उससे साक्षात्कार नहीं हो सका तब दूसरी बार फोटोग्राफर और पंचायत समिति सूरतगढ़ के कृषि प्रसार अधिकारी के साथ गया, तब द्रोपदी अपने कच्चे घर के बरामदे में पलंग पर लेटी हुई थी। जब उससे कहा गया कि कोई उससे मिलने के लिए आए हैं तब पहले तो बाहर आने से इन्कार कर दिया। जब पिता ने आग्रह किया कि पंचायत समिति और जिले के अधिकारी आए हैं तब बड़े अनमने ढंग से लुंगी और कमीज पहने यह युवक नुमा युवती हमारे सामने आकर कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई। हम उसे ऊपर से नीचे तक देख ही रहे थे कि वह बोली 'हां कै है? मेरी इच्छा की कि क्यों न उसे उस समय सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञों को दिखाया जाए, शायद यौन परिवर्तन का ही मामला हो। जब उससे कहा गया कि सूरतगढ़ में कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं, वह साथ चले, अपने पिता को भी साथ ले चले, यहां जीप से ही वापस पहुंचा देंगे किंतु वहां जाने के लिए उसने साफ इन्कार कर दिया।



पुरुष वेष में द्रोपदी

आखिर जो बातचीत हुई उसका सार यही है कि द्रोपदी को औरतों के काम पसंद नहीं। वह मर्दों की भाँति ही रहना चाहती है। उसके दो भाई और 6 बहने हैं। एक बहिन भगवान को प्यारी हो गई, एक सुसुराल गई और वह स्वयं सुसुराल से लौट कर वापस आ गई। 25 वर्षीय द्रोपदी ही सब भाई बहनों में बड़ी है। माता-पिता के और अपने खेत में काम करना तथा छोटे भाई बहनों के पालन-पोषण में ही उसे आनंद आता है।

द्रोपदी अनपढ़ है, किंतु न जाने स्त्री स्वतंत्रता के युग में उसे जमाने की हवा लगी है अथवा कोई मनोवैज्ञानिक व शारीरिक कारण है जिससे इस असामान्य दिखाई देने वाले जीवन को ही सामान्य समझकर खुश है।

जिला जन सम्पर्क अधिकारी
श्री गंगानगर (राज०)





सैन्ट पाल्स स्कूल, उदयपुर के छात्रों ने अनेक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए और 17,500 रु. एकत्रित किए। इस रकम से उदयपुर जिले के टूम गांव में एक शिविर लगा जो एक सप्ताह तक चला। इस अवधि में गरीब हरिजन किसानों की जमीन पर छुंए खोदे गए जिससे इन गरीब किसानों को भूमि से अधिक पैदावार मिलने की आशा है। इन 250 छात्रों के शिविर की बड़ी सराहना हुई और गांव वालों ने छात्रों के प्रति आभार प्रकट किया।